नई दिल्ली । शुक्रवार, 10 जुलाई, 2026
आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083
वर्ष :12, अंक :185 / मूल्य 3.00 रुपए । पृष्ठ 12

दैनिक
विश्व केसरी
सिर्फ पत्रकारिता...
नई दिल्ली संस्करण
vishwakesari.com
@vishwakesariTV
@vishwakesari
vishwa_kesari_official
आर. एन. आई. संख्या डीईएलएच आईएन/2015/61415

@ खेल चित्रा के. सोमन : कड़ी मेहनत से बनाई पहचान...
@ विचार भारत-ऑस्टेलिया के बीच जो समझौते हुए हैं उससे...
@ व्यापार भारी गिरावट से उबरा बाजार, सेंसेक्स 238 अंक...

प्रवासी भारतीयों के बीच पीएम मोदी, भारत की उपलब्धियों और भविष्य पर रखा खाका

6जी तकनीक पर भी तेजी से कर रहा काम

एजेंसी ■ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश 'चिप्स से लेकर शिप्स तक' एक मजबूत विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व हासिल करने के लिए 6जी तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कुछ सौ स्टार्टअप्स से शुरू हुआ सफर अब 2 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स तक पहुंच चुका है। देश में हर महीने 4,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं।

उन्होंने भारत के युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और नवाचार की बदौलत भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स का विकास अब केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के लगभग हर जिले तक इसका विस्तार हो चुका है। उन्होंने बताया कि आज रक्षा (डिफेंस) और अंतरिक्ष (स्पेस) जैसे

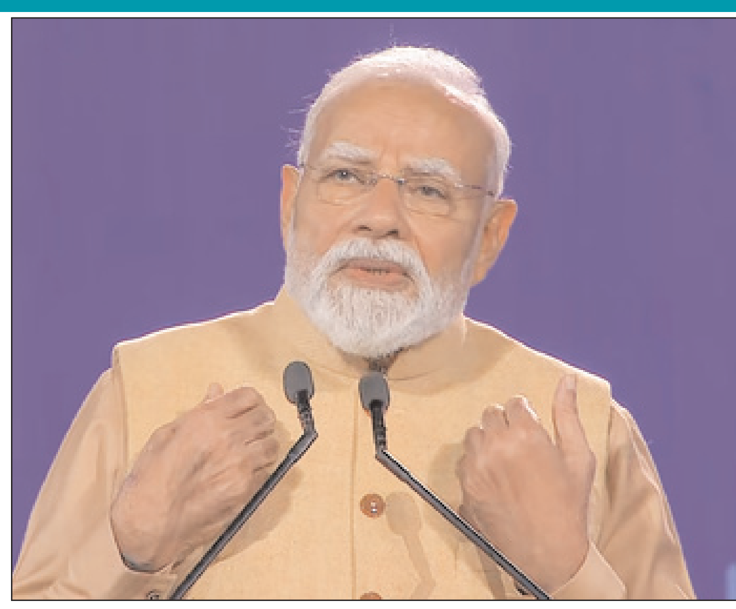

अत्याधुनिक क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत का एक स्पेस स्टार्टअप अपने ही रॉकेट से अपना उपग्रह (सैटेलाइट) लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत गगनयान मिशन और अपने स्वयं के स्पेस स्टेशन की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के बड़े सपनों और ऊंची आकांक्षाओं की सबसे मजबूत नींव देश के लोग हैं। 'वी द पीपल' और 'नागरिक देवो भव:' का मंत्र आज देश के सुशासन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन चुका है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकानों पर विस्फोट हो रहे थे और उनकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी।'

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 की अपनी पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा को याद करते हुए कहा कि वह 28 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी। उस समय उन्होंने भारतीय समुदाय से कहा था कि अगली यात्रा के लिए उन्हें फिर 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पिछले 12 वर्षों में यह मेरी ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा है। एक तरह से यह हैट्रिक है। यह भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की नई ऊंचाइयों को दर्शाता है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय मुझे नहीं, बल्कि आप सभी भारतीयों को जाता है। भारतीय प्रवासी समुदाय ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मेलबर्न पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय ने 'मोदी-मोदी' और 'वंदे मातरम' के नारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेलबर्न का मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन भारतीय समुदाय के स्वागत की गर्मजोशी अविस्मरणीय रही।

ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव

बंदर अब्बास पोर्ट सिटी के तटीय इलाकों में हुए धमाके

एजेंसी ■ तेहरान

ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट सिटी के तटीय इलाकों में गुरुवार दोपहर कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक, ये आवाजें स्थानीय समय के अनुसार करीब दोपहर 2 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे) शहर के दक्षिणी तट के आसपास सुनी गईं। माना जा रहा है कि ये धमाके खाड़ी क्षेत्र और होर्मुज स्ट्रेट के कुछ हिस्सों में हुई गोलीबारी या सैन्य कार्रवाई के कारण हुए।

इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि गुरुवार सुबह अमेरिका के हमले में खुजेस्तान प्रांत के उसके तीन सैनिक मारे गए। वहीं, बहरीन और कुवैत ने गुरुवार को बताया कि उनके हवाई रक्षा तंत्र ने ईरान की ओर से किए गए हवाई हमलों को रोक दिया और उन्हें नष्ट कर दिया।

बहरीन डिफेंस फोर्स (बीडीएफ) ने एक बयान में कहा कि ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जरिए आम नागरिकों को निशाना बनाना जारी रखा है। उसने इसे देश के खिलाफ एक 'लगातार शत्रुतापूर्ण रवैया' बताया। बीडीएफ ने कहा कि उसकी सभी सैन्य इकाइयां देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे हमलों के बाद मिले किसी भी अनजान या संदिग्ध सामान के पास न जाएं और उसे हाथ न लगाएं। बहरीन ने कहा कि आम लोगों और निजी संपत्ति को निशाना बनाने के लिए मिसाइल और ड्रोन का जानबूझकर इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है।

उधर, कुवैत की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि सेना ने तड़के तीन बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल और दस ड्रोन को रोक दिया। हालांकि, इनके मलबे से कई जगहों पर नुकसान हुआ और एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसकी हालत स्थिर बताई गई है। गुरुवार सुबह पूरे कुवैत में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। हमलों के दौरान गिरे मलबे को हटाने के लिए विस्फोटक निष्क्रिय करने वाली टीमें तैनात की गईं। इसके अलावा, कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों की निंदा करते हुए उन्हें कुवैत की संप्रभुता का 'खुला उल्लंघन', उसकी सुरक्षा और स्थिरता के लिए 'सीधा खतरा' और अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन बताया।

इससे पहले अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा था कि उसकी सेनाओं ने ईरान की होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर हमला करने की क्षमता को कम करने के लिए एक और दौर के हमले पूरे किए हैं। यह लगातार दूसरे दिन की गई ऐसी कार्रवाई थी।

20वीं शताब्दी के अंत तक देश में केवल एक एम्स था, आज संख्या बढ़कर 23 हो गई : जेपी नड्डा

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को हैदराबाद के बीबीनगर में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एम्स बीबीनगर की प्रगति की समीक्षा की। एम्स की स्थापना भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के सातवें चरण के तहत वर्ष 2019 में की गई थी। यह परियोजना जून 2022 में 1,110.55 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई थी।

सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र ने बुनियादी ढांचे और क्षमता विस्तार के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने बताया कि 20वीं शताब्दी के अंत तक देश में केवल एक एम्स था, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में छह अतिरिक्त एम्स स्थापित किए गए। तब से अब तक 16 नए एम्स जुड़ चुके हैं, जिससे देश भर में इनकी कुल संख्या 23 हो गई है। इनमें से 18 एम्स पहले से ही कार्यरत हैं, जबकि शेष विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं। नड्डा ने कहा कि सरकार ने तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करते हुए द्वितीयक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करके एक समान और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ढांचा विकसित किया है। उन्होंने बताया कि देश में अब 1.85 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो लगभग 1.5 अरब लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 से बढ़कर वर्तमान में 820 हो गई है। संस्थान के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें अवसंरचना विकास, चिकित्सा शिक्षा, रोगी देखभाल, अनुसंधान गतिविधियां और संस्थान के सामने आने वाली चुनौतियां शामिल थीं। एम्स बीबीनगर में वर्तमान में 132 संकाय सदस्य और 133 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर हैं। संस्थान की स्थापना के तुरंत बाद एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू हुआ और दो बैच पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं।

तृणमूल के तीन पूर्व राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हुए

एजेंसी ■ कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सदस्य गुरुवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। तीनों राज्यसभा सांसदों ने पिछले महीने संसद के उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं (सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक) का स्वागत किया और उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा।

भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि रॉय, देव और बराइक को भाजपा में शामिल होने की अनुमति देना एक अपवाद माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा तृणमूल के किसी भी सदस्य के लिए अपने दरवाजे खोल देगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीनों नेताओं का रिकॉर्ड बेदाग है और तृणमूल में रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है।

राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें तेज हैं कि भाजपा आगामी राज्यसभा उपचुनावों के लिए इन तीनों नेताओं को फिर से नामांकित कर सकती है। हालांकि, भट्टाचार्य ने इस संभावना की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रॉय ने 8 जून को राज्यसभा से इस्तीफा दिया, उसके बाद देव ने 10 जून को और बराइक ने 11 जून को इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद बराइक ने मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा की थी, जबकि देव ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी। रॉय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से काफी पहले से तृणमूल नेतृत्व के आलोचक रहे थे।

अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी। पार्टी में उन्हें दरकिनार कर दिया गया और अंततः उन्होंने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया।

महिला सशक्तिकरण के लिए ज्ञान साझाकरण सहपाठी-शिक्षा, सुदृढ़ीकरण, भारत की दो नई पहल

कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक का समापन

एजेंसी ■ नई दिल्ली

भारत की वर्ष 2026 में ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक आज केरल के कोच्चि में संपन्न हो गई, जो महिला नेतृत्व वाले विकास पर ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 6 से 9 जुलाई 2026 तक चले चार दिनों के सम्मेलन में ब्रिक्स महिला कार्य समूह और ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक हुई। इस अवसर पर ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की साझा प्राथमिकताओं पर विमर्श किया।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंत्रिस्तरीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देश विभिन्न भौगोलिक,

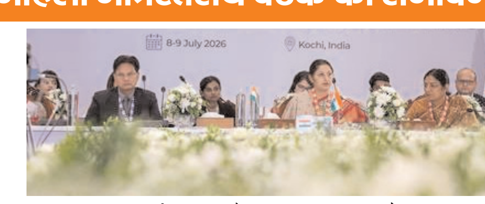

सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, पर उनमें महिला सशक्तिकरण से संबंधित कई समान चिंताएं साझा हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय ट्रैक जैसे मंचों के महत्व को दर्शाती हैं, जो सदस्य देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और सहयोग सुदृढ़ करने में सहायक हैं।

महिला एवं बाल विकास सचिव श्अनिल मलिक ने समापन संबोधन में भारत की अध्यक्षता के दौरान हुए विमर्श के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स संयुक्त महिला मंत्रिस्तरीय वक्तव्य अपनाना जाना समान चुनौतियों का मुकाबला करने के हमारे साझे संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इस वर्ष महिला मंत्रिस्तरीय बैठक में ऐतिहासिक रूप से महिला ट्रैक में पहली बार संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया, जो सभी क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने की ब्रिक्स सदस्य देशों की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है।

ब्रिक्स में महिला ट्रैक एक विशेष कार्य योजना और मंच है जो सदस्य देशों के बीच लैंगिक समानता, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। बैठक में ब्रिक्स महिला ट्रैक के तहत दीर्घकालिक सहयोग बढ़ाने के भारत द्वारा प्रस्तावित दो पहल का स्वागत किया गया।

महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में सीबीआई ने दाखिल किए छह आरोप पत्र; मुख्य सरगना नामजद

एजेंसी ■ नई दिल्ली

देश के सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बहुचर्चित महादेव ऐप भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी मामले में छह नए आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किए हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में छह मुख्य आरोपियों—असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज अहूजा को नामजद किया है। इन सभी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने की गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन प्राथमिक आरोपों के साथ ही, जांचकर्ताओं ने इस घोटाले के मुख्य सरगनाओं—सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल—के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी अदालत के समक्ष पेश किए हैं, जिन्हें पहले ही आरोपित किया जा चुका है।

इस जांच के एक अन्य समानांतर हिस्से में, केंद्रीय एजेंसी ने 66 व्यक्तियों के खिलाफ पांच और आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इस बड़ी कानूनी कार्रवाई में चंद्राकर और उप्पल के अलावा 'सट्टेबाजी सिंडिकेट पैनल' के कई प्रमुख सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने अपराध की काली कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) को ठिकाने लगाने और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन पांच आरोप पत्रों को भारतीय दंड संहिता और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत दाखिल किया गया है।

सिंडिकेट का नेटवर्क: महादेव ऑनलाइन बुक नेटवर्क को भारत में अब तक पकड़े गए सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट में से एक माना गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आक्रामक इस्तेमाल के जरिए इस नेटवर्क को देशव्यापी रूप दिया गया, जिसने देश के लाखों उपयोगकर्ताओं को अपनी चपेट में ले लिया। केंद्रीय एजेंसी की जांच से यह साफ हुआ है कि यह सिंडिकेट बेहद योजनाबद्ध और बहु-स्तरीय तरीके से काम कर रहा था। इस नेटवर्क ने देश भर में अवैध सट्टेबाजी पैनल स्थापित किए, डिजिटल विज्ञापनों के जरिए नए यूजर्स को जोड़ा और सट्टेबाजी के बाजार संचालित किए। इन अवैध गतिविधियों से होने वाली मोटी कमाई को पहले 'म्यूल अकाउंट्स' (फर्जी बैंक खातों) के एक जटिल जाल के माध्यम से वैध दिखाने की कोशिश की गई और अंतत: इस धन को विदेशों में ट्रांसफर कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा लोक सेवकों (सरकारी अधिकारियों) को संरक्षण राशि और रिश्वत के तौर पर दिया जाता था। महादेव ऐप के प्रमोटर और उनके कई प्रमुख सहयोगी कुछ साल पहले ही भारत से फरार होकर पश्चिम एशियाई देशों में शरण ले चुके हैं, और वे वहीं से बैठकर भारत के बाहर से इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं।

इन भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद ली जा रही है। विदेश भाग चुके चार मुख्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस (अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट) पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही, भारतीय कानून के तहत इन व्यक्तियों को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे देश में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह जांच अभी समाप्त नहीं हुई है।

ई20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों को केंद्रीय मंत्री ने किया खारिज

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन (ई20) को लेकर उठ रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि ई20 पेट्रोल पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया गया, सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित ईंधन है। उन्होंने आरोप लगाया कि ई85 ईंधन के अनुकूल वाहनों की शुरुआत के बाद एथेनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने का अभियान तेज हो गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में मंत्री ने कहा कि भारत में अप्रैल 2023 से ई15, अप्रैल 2024 से ई19 और अप्रैल 2025 से ई20 ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर इसके उपयोग के बावजूद कोई बड़ी

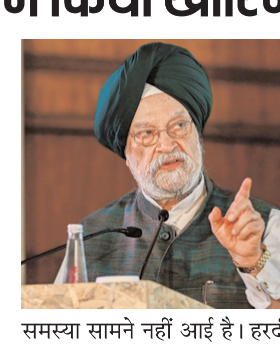

समस्या सामने नहीं आई है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'देश में 20 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन और 20 लाख से ज्यादा चारपहिया वाहन कई वर्षों से सफलतापूर्वक ई20 ईंधन पर चल रहे हैं। इसके बावजूद, अचानक एथेनॉल मिश्रण के खिलाफ अभियान तेज हो गया है।'

उन्होंने दावा किया कि 5 जून को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए ई85 ईंधन लॉन्च किए जाने के बाद इस तरह की आलोचनाएं बढ़ने लगीं।

योगी सरकार में समस्याओं का त्वरित समाधान, 89.41 लाख रुपए के जीपीएफ का कराया भुगतान

विश्व केसरी

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे आम नागरिकों के साथ-साथ कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों की समस्याओं का भी त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में देवीपाटन मंडल में मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने 'संध्या संवाद' कार्यक्रम के जरिये लोगों की समस्याओं का समाधान कराया।

देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती में आयोजित संध्या संवाद कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आए, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ एवं अन्य सेवा संबंधी देयों का भुगतान कराया गया। इस पहल के तहत कुल 89 लाख 41 हजार 612 रुपए की जीपीएफ धनराशि संबंधित कर्मचारियों के खातों में पहुंचाई गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरे भुगतान मिलने के बाद खुशी से खिल उठे।

सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं कि जनशिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न बनकर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किया जाए। उनकी प्राथमिकता है कि आम जनता से लेकर कर्मचारियों तक किसी भी व्यक्ति को अपने वैधानिक अधिकारों के लिए भटकना न पड़े। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मंडल में संध्या संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से प्रशासन सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है।

'संध्या संवाद' कार्यक्रम में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शिकायत रखी कि उनका जीपीएफ तथा अन्य सेवा संबंधी भुगतान लंबित है। इस पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी श्रावस्ती अन्नपूर्णा गर्ग ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया। जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं तेजी से पूरी कराईं।

मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति नए तरीके से देश के नव निहालों को नवनिर्माण की नित नई राह दिखाएगी: बृजमोहन अग्रवाल

विश्व केसरी

दिल्ली । रायपुर के सांसद और छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति नए तरीके से देश के नव निहालों को नवनिर्माण की नित नई राह दिखाएगी। बृजमोहन अग्रवाल बृहस्पतिवार को देश के जाने-माने वाणिज्यिक संगठन एसोचेम द्वारा विकसित भारत शिक्षा अभियान पर राजधानी दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में आयोजित 18 वीं नेशनल एजुकेशन लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट समिट 2026 में शिक्षा जगत में सक्रिय संस्थाओं और हस्तियों को सम्मानित करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रट्टा मारने की पुरानी प्रणाली को जड़ से खत्म किया है। अब भारतीय शिक्षा प्रणाली का ध्यान इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक युवाओं के अपस्किलिंग, स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने पर है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक नयी पहचान देने का काम करेगा। समारोह के विशिष्ट अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत की थीम पर हमको140 करोड़ लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए देश के सुदुर क्षेत्रों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हुए शिक्षा के स्तर को और ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी करना होगा तभी सभी लोगों को शिक्षित करते हुए हमारा देश उचित ढंग से और विकसित हो पाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखण्ड और ओड़िशा के सुदूरवर्ती स्थलों का हवाला देते हुए वंचितों के शैक्षिक विकास के लिए सघन प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमें शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत अभावग्रस्त संस्थाओं और गैरसरकारी संगठनों को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराना होगा ताकि सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके।

तेलंगाना: अमोनिया रिसाव के कारण आरएफसीएल फिर से बंद, यूरिया उत्पादन ठप

विश्व केसरी

हैदराबाद। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में स्थित रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) को अमोनिया पाइपलाइन में रिसाव के कारण बंद कर दिया गया है।

रिसाव के कारण प्लांट की सभी इकाइयों के बंद होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी में यूरिया उत्पादन ठप हो गया है।

सूत्रों के अनुसार, तकनीकी खराबी के कारण रिसाव हुआ। समस्या का समाधान न हो पाने के कारण प्लांट को बंद कर दिया गया। समस्या के समाधान के बाद उत्पादन फिर से शुरू होने में कम से कम एक सप्ताह का समय लग सकता है।

यूरिया उत्पादन ठप होने से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पांच अन्य राज्यों को उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है।

इसके साथ ही खरीफ फसल के मौसम में किसानों को आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है।यह इस साल दूसरी बार है जब अमोनिया रिसाव के कारण आरएफसीएल प्लांट को बंद करना पड़ा है। मार्च में भी प्लांट एक सप्ताह के लिए बंद रहा था।

इस प्लांट की क्षमता 3,850 टन प्रतिदिन है, लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण गैस की कमी के चलते यह कुछ समय से 50 प्रतिशत क्षमता पर ही चल रहा था।

चूंकि आरएफसीएल तेलंगाना के लिए यूरिया का एकमात्र स्रोत है, इसलिए राज्य सरकार केंद्र से इस प्लांट से उत्पादित संपूर्ण यूरिया को तेलंगाना को आवंटित करने की मांग कर रही है।

इस बीच, तेलंगाना सरकार ने राज्य भर के किसानों के लिए रियायती यूरिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक अभिनव कदम उठाया है। पारदर्शिता बढ़ाने और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कृषि विभाग ने राज्य भर के सभी मीसेवा केंद्रों पर यूरिया बुकिंग सेवा शुरू की है।
जो किसान उर्वरक बुकिंग ऐप के माध्यम से यूरिया बुक नहीं कर पा रहे हैं, वे अपने निकटतम मीसेवा केंद्र पर जाकर ऑपरेटर की सहायता से यूरिया बुक कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री दुद्दिला श्रीधर बाबू के नेतृत्व में कार्यरत मीसेवा, कृषि विभाग के सहयोग से इस नई पहल को शुरू कर रही है।

अमरनाथ यात्रा: एलजी मनोज सिन्हा ने पंथा चौक यात्री ट्रांजिट कैंप का किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं को हर सुविधा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

विश्व केसरी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को श्रीनगर स्थित पंथा चौक यात्री ट्रांजिट कैंप और यात्री निवास का दौरा कर चल रही श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और श्रद्धालुओं से बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि भगवान शिव के प्रत्येक श्रद्धालु को 24 घंटे बेहतर सुविधाएं और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि पंजीकरण से लेकर आवास, भोजन और अन्य आवश्यक सेवाओं तक किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर आने वाले प्रत्येक यात्री का प्रवास सुरक्षित, सुगम और आध्यात्मिक अनुभव से भरपूर बनाना सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

निरीक्षण के दौरान एलजी ने आवास, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले एक सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इसे देश की आध्यात्मिक विरासत के लिए शुभ संकेत बताते हुए कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को देशभर के श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय कारीगरों को सम्मान मिलेगा और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

उपराज्यपाल ने जिला प्रशासन, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, पुलिस, सुरक्षा बलों और सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने यात्रा के दौरान प्रभावी भीड़ प्रबंधन, सुगम पंजीकरण प्रक्रिया और श्रद्धालुओं तक समय पर आवश्यक सूचनाएं पहुंचाने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

नोएडा: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, लोडर और बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत, तीन घायल

विश्व केसरी

नोएडा। नोएडा के थाना फेस-2 क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने सब्जियों से भरे लोडर वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोडर के साथ-साथ सड़क किनारे चल रही एक मोटरसाइकिल भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार को थाना फेस-2 क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने सब्जियों से भरे लोडर वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के प्रभाव से लोडर अनियंत्रित हो गया और उसकी चपेट में पास से गुजर रही एक मोटरसाइकिल भी आ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही फेस-2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। हादसे में लोडर पर सवार दीपक (16 वर्ष) पुत्र राजेंद्र, निवासी ग्राम लोथर, जनपद बदायूं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उपचार के दौरान राजवीर (50 वर्ष) पुत्र वासुदेव, निवासी ग्राम सुरौरा, थाना गुन्नौर, जनपद संभल ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

इस दुर्घटना में लोडर चालक अशोक कुमार (56 वर्ष) निवासी अहमदपुर, शामली, आकाश (31 वर्ष) निवासी रसूलपुर, संभल, शंकर (24 वर्ष) निवासी सुरौरा, संभल तथा मोटरसाइकिल सवार अभिषेक राय (29 वर्ष) निवासी सिरसी, जनपद संतकबीरनगर घायल हुए।

महाराष्ट्र में यूसीसी की कवायद को महायुति का समर्थन, नितेश राणे बोले- संविधान के अनुसार होगा काम

विश्व केसरी

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए सात सदस्यीय समिति गठित किए जाने के बाद महायुति सरकार के नेताओं ने इस पहल का स्वागत किया है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे और शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा कि राज्य सरकार संविधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ रही है और सभी निर्णय संवैधानिक दायरे में ही लिए जाएंगे। इस दौपान, अब्दुल सत्तार ने एकनाथ शिंदे और शरद पवार की हालिया मुलाकात को लेकर चल रही सियासी अटकलों को भी खारिज किया।

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लेख है और महायुति सरकार उसी संवैधानिक दिशा में आगे बढ़ रही है। डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के अनुसार ही देश चलेगा और इसी आधार पर सरकार निर्णय ले रही है। संविधान सर्वोपरि है और देश में सभी कानून उसी के अनुरूप लागू होने चाहिए। जो लोग भारत में शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत में केवल संविधान का शासन चलेगा। महायुति सरकार की यह पहल संविधान और उसकी मूल भावना के अनुरूप है।

वहीं, शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने भी सात सदस्यीय समिति के गठन का स्वागत करते हुए कहा कि देश का संचालन संविधान की चौखट में रहकर ही होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कानून बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी निर्णय से धार्मिक भावनाएं प्रभावित न हों और यदि कोई विषय राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ाया जा रहा हो तो उस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

डॉ. आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की मर्यादा में रहकर ही कोई भी निर्णय लिया जाना चाहिए।महाराष्ट्र में मिसिंग लिंक परियोजना को लेकर उठे विवाद पर भी अब्दुल सत्तार ने प्रतिक्रिया दी।

न्यूयॉर्क से रवाना हुई आईएनएस सुदर्शिनी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने लहराया तिरंगा

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की आईएनएस सुदर्शिनी ने अमेरिका में न्यूयॉर्क से आगे का सफर शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क में ठहरने के दौरान नौसेना के पोत ने न केवल भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक, सांस्कृतिक और जन-जन के संबंधों को भी नई मजबूती प्रदान की।
सुदर्शिनी स्वदेशी रूप से निर्मित तीन मस्तूल वाला बार्क पोत है। यह भारतीय नौसेना के 10 महीने लंबे अंतर महासागरीय अभियान 'लोकायन 2026' पर है। इस यात्रा के एक हिस्से के रूप में सुदर्शिनी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और सेल फोर्थ 250 समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह आयोजन दुनिया भर की नौसेनाओं और पारंपरिक नौकायन पोतों की भागीदारी के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

असम के समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की समयसीमा तय नहीं: मंत्री पेगु

विश्व केसरी

गुवाहाटी। असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने संबंधी लंबित प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के विचाराधीन है। शिक्षा और जनजातीय मामलों के मंत्री रानोज पेगू ने गुरुवार को कहा कि चूंकि यह मामला केंद्र के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए प्रक्रिया पूरी होने की कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती।

असम विधानसभा सत्र के दौरान विधायक चक्रधर गोगोई द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पेगू ने कहा कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से लिया जाता है।

उन्होंने सदन को सूचित किया कि असम सरकार को सौंपी गई प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वह अपनी सिफारिशें केंद्र को भेजने की प्रक्रिया में है।

मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी ताकि यह आकलन किया जा सके कि छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से असम में मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा, आरक्षण लाभ और अन्य अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

इस मुद्दे की व्यापक जांच के लिए असम सरकार ने मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया था। पेगू ने बताया कि जीओएम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नवंबर 2025 में असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी गई थी।

उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट, राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ, अब आगे विचार के लिए केंद्र सरकार को भेजी जा रही है।

पेगू ने दोहराया कि राज्य सरकार ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का है।

प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की संभावित तिथि के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि असम सरकार इस मामले में कोई समयसीमा नहीं बता सकती, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है।

रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल सख्त

बोले- '20 मिनट का सफर एक घंटे में, व्यवस्था सुधारें अधिकारी'

विश्व केसरी

रायपुर (संवाददाता)। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर का ट्रैफिक प्रबंधन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है और संबंधित विभाग का 'ट्रैफिक सेंस' काम नहीं कर रहा है। इसका खामियाजा आम नागरिकों को रोजाना लंबे जाम और घंटों की देरी के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

बैठक के दौरान सांसद ने कहा कि कुछ वर्ष पहले शहर के किसी भी हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब वही दूरी तय करने में एक घंटे या उससे अधिक समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि रायपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में यह स्थिति चिंताजनक है और यातायात व्यवस्था में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

बृजमोहन अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर प्रतिदिन ट्रैफिक जाम लगता है, वहां संबंधित थानों के पुलिसकर्मी सड़क पर नजर नहीं आते। उन्होंने पुरानी बस्ती और पंडरी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि इन इलाकों में रोजाना जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन नहीं दिखता। उन्होंने अधिकारियों से नियमित मॉनिटरिंग और मौके पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सांसद ने शहर के कई पेट्रोल पंपों के सामने लगाए गए सीमेंट बैरिकेडों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इन बैरिकेडों के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित होती है और अनावश्यक जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बैरिकेडों को आवश्यक दूरी पर हटाया जाए या व्यवस्थित किया जाए ताकि वाहन आसानी से अंदर-बाहर आ सकें।

बैठक में वीआईपी रोड का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सांसद ने कहा कि राम मंदिर चौक से एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर अक्सर लंबा जाम लगता है। एक बार वाहन इस मार्ग पर फंस जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ट्रैफिक अधिकारियों को सर्विस रोड पर लगाई गई अनावश्यक बैरिकेडिंग हटाने और जरूरत के अनुसार सड़क पर कट विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे वाहनों का दबाव कम हो सके और यातायात सुचारु रूप से संचालित हो।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने सांसद को भरोसा दिलाया कि शहर के चिन्हित जाम वाले स्थानों का जल्द निरीक्षण किया जाएगा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सांसद ने कहा कि रायपुर की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन को आधुनिक और प्रभावी बनाना समय की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों को रोजाना जाम की परेशानी से राहत मिल सके।

राज्य में स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

2027-28 से 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र

विश्व केसरी

रायपुर (संवाददाता)। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक संचालित किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश जारी कर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू करने को कहा है।

अभी तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 16 जून से 30 अप्रैल तक चलता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रणाली समाप्त हो जाएगी और पूरे शैक्षणिक वर्ष का संचालन अप्रैल से मार्च तक किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों के अनुरूप हो जाएगी।

नई व्यवस्था में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विद्यार्थियों को पहले की तरह 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां मिलती रहेंगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि 1 अप्रैल को ही नए सत्र की शुरुआत के साथ शाला प्रवेश उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसी दिन से विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलें, स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य छात्रहितैषी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सत्र शुरू होने के पहले दिन से ही सभी आवश्यक संसाधन स्कूलों और विद्यार्थियों तक पहुंच जाएं।

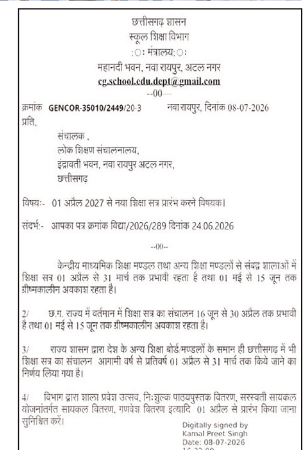
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:०: मंत्रालय :०:
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
cg.school.edu.dept@gmail.com
--00--

क्रमांक GENCOR-35010/2449/20-3 नवा रायपुर, दिनांक 08-07-2026

प्रति,
संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
छत्तीसगढ़

विषय:- 01 अप्रैल 2027 से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ करने विषयक।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक विद्या/2026/289 दिनांक 24.06.2026

--00--

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा अन्य शिक्षा मण्डलों से संबद्ध शालाओं में शिक्षा सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रभावी रहता है तथा 01 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है।

2/ छ.ग. राज्य में वर्तमान में शिक्षा सत्र का संचालन 16 जून से 30 अप्रैल तक प्रभावी है तथा 01 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है।

3/ राज्य शासन द्वारा देश के अन्य शिक्षा बोर्ड/मण्डलों के समान ही छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा सत्र का संचालन आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4/ विभाग द्वारा शाला प्रवेश उत्सव, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, सरस्वती सायकल योजनांतर्गत सायकल वितरण, गणवेश वितरण इत्यादि 01 अप्रैल से प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Kamal Preet Singh
Date: 08-07-2026
16:32:00
(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि इस बदलाव से किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य योजनाओं के वितरण में होने वाली देरी खत्म होगी। सत्र की शुरुआत से ही नियमित पढ़ाई शुरू होने से शिक्षण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बनेगी, विद्यार्थियों का शैक्षणिक समय बेहतर तरीके से उपयोग होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

संक्षिप्त खबरें

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 15 इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर के तबादले

विश्व केसरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के 15 निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) और एक उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) का तबादला किया गया है। इस संबंध में आदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। तबादला सूची में दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, सूरजपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर-रामानुजगंज, बस्तर, धमतरी, पुलिस मुख्यालय तथा राज्य नगर सैनिक संगठन सहित विभिन्न जिलों और इकाइयों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्थानांतरित अधिकारियों में निरीक्षक वीरेंद्र आनंद गांगुली, संतोष कुमार शर्मा, श्रीकांत पटेल, जगन्नाथ साहू, सुखदेव दुबे, रवि कुमार कुर्रे, शिवशंकर सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। वहीं उप निरीक्षक प्रेम कुमार सिंह का भी तबादला किया गया है। सभी अधिकारियों को शीघ्र नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने किया 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला

विश्व केसरी

रायपुर (संवाददाता)। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पांच अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महानदी भवन से जारी आदेश में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन को पद से हटाकर मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि देवांगन को करीब दो माह पूर्व ही जीपीएम जिले का कलेक्टर बनाया गया था।

सरकार ने उनकी जगह तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक विजय दयाराम के. को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का नया कलेक्टर नियुक्त किया है। इस फेरबदल को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जारी आदेश के अनुसार, आईएएस अधिकारी हेमंत रमेश नंदनवार (2020 बैच) को महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) पद से हटाकर संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के प्रबंध संचालक (एमडी) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं, दुर्ग नगर निगम के आयुक्त सुमित अग्रवाल (2021 बैच) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण (स्डा) नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के साथ ही रिमिजियस एक्का को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

थमा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम रायपुर के कई चौराहों पर सिग्नल बंद

विश्व केसरी

रायपुर (संवाददाता)। राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है। शहर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन प्रभावित होने से करीब एक दर्जन प्रमुख चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, जबकि कई सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं। इससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

जानकारी के अनुसार, आईटीएमएस का संचालन कर रही कंपनी एलएंडटी ने भुगतान नहीं मिलने के कारण रखरखाव और संचालन का कार्य रोक दिया है। नए ठेके की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से सिस्टम की मरम्मत भी ठप पड़ी है।

इसके चलते शहर के कई व्यस्त चौराहों पर सिग्नल निष्क्रिय हैं और ट्रैफिक पुलिस को मैन्युअल रूप से यातायात नियंत्रित करना पड़ रहा है।

सिग्नल बंद रहने से पीक आवर्स में कई स्थानों पर लंबा जाम लग रहा है। वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल यात्रियों को भी सड़क पार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो बारिश के मौसम और बढ़ते यातायात दबाव के बीच हादसों की आशंका और बढ़ सकती है।

तीन रेलवे ओवरब्रिजों में आई दरारें, डॉ. रमन सिंह ने रेल मंत्री से की जांच की मांग

विश्व केसरी

रायपुर (संवाददाता)। राजनांदगांव जिले में हाल ही में बने तीन रेलवे ओवरब्रिजों में दरारें आने का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस मामले को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने पुलों की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच कराने और लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

डॉ. रमन सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि जिले के बरगा, आलीवारा और मुसरा में बने नए रेलवे ओवरब्रिज बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद पुलों में बड़ी दरारें

आना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने बताया कि दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन के नागपुर मंडल के डोंगरगढ़-राजनांदगांव रेलखंड पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से इन ओवरब्रिजों का निर्माण कराया गया था। इनका लोकार्पण जून 2026 में हुआ था। इसके बाद 4 और 5 जुलाई को हुई तेज बारिश के बाद पुलों में 60 से 70 फीट तक लंबी और करीब 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें दिखाई दीं। दरारों के कारण इन पुलों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल इन्हें आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक निर्माण के शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही इस तरह की समस्या सामने आना बेहद गंभीर विषय है। इससे लोगों में नाराजगी भी है। उन्होंने रेल मंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और निर्माण से जुड़ी एजेंसी, ठेकेदार, सलाहकार और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय की जाए। दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रभावित ओवरब्रिजों का तुरंत सुरक्षा परीक्षण कराने और जरूरत के अनुसार मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने का भी आग्रह किया है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके। डॉ. रमन सिंह ने उम्मीद जताई कि रेल मंत्रालय जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मामले में जल्द कार्रवाई करेगा।

मुआवजे में असमानता, आदिवासी श्रमिकों के परिजनों को कम राशि मिलने का आरोप

विश्व केसरी

रायपुर (संवाददाता)। उरला थाना क्षेत्र के बेंद्री स्थित 3डी इनोवेशन फैक्ट्री में हुए भीषण ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट में तीन श्रमिकों की मौत के बाद अब मुआवजे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि मृतकों के परिजनों को समान मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे आदिवासी श्रमिकों के साथ भेदभाव किए जाने के सवाल उठने लगे हैं।

7 जुलाई की शाम हुए इस हादसे में मध्यप्रदेश के मंडला जिले के आदिवासी श्रमिक लाल सिंह और कमल सिंह मरावी तथा छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा निवासी अरुण पांडे की मौत हो गई थी। विस्फोट इतना भीषण था कि तीनों श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू

की और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। गुरुवार को उनके गृह ग्राम में अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा था कि कंपनी प्रबंधन मृतकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा देगा। लेकिन परिजनों को मिली राशि को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, अरुण पांडे के परिजनों को 29 लाख रुपये का चेक और 1 लाख रुपये नकद, कुल 30 लाख रुपये दिए गए। वहीं मंडला के दोनों आदिवासी श्रमिकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का चेक और 1-1 लाख रुपये नकद, यानी कुल 21-21 लाख रुपये ही दिए गए। इस अंतर को लेकर कंपनी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को समान मुआवजा देने की बात कही थी, तो फिर दो परिवारों को कम राशि क्यों दी गई। इसे लेकर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा और मुआवजा नीति पर भी चर्चा तेज हो गई है। बीरगांव के बजरंग दल नेता बीरेंद्र विश्वकर्मा ने भी इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि यदि एक मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपये दिए गए हैं, तो अन्य दो मृत आदिवासी श्रमिकों के परिवारों को केवल 21-21 लाख रुपये देना समझ से परे है।

कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर की मांग

विश्व केसरी

रायपुर (संवाददाता)। नकटी गांव में 85 गरीब परिवारों के मकान ध्वस्त किए जाने के मामले में गुरुवार को प्रभावित परिवार बड़ी संख्या में माना थाना पहुंचे और तत्कालीन कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पीड़ितों के समर्थन में प्रदर्शन किया।

पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने थाना परिसर के बाहर नारेबाजी करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर नया रायपुर नहीं जाएंगे और अपने मूल गांव में ही सम्मानजनक पुनर्वास चाहते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने सीएसपी लंबोदर

पटेल एवं थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर आरोप लगाया कि भारी बारिश के दौरान अमानवीय तरीके से मकानों को तोड़ा गया, जिससे दर्जनों परिवार बेघर हो गए। शिकायत में घरेलू सामान, अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी सामग्री के नुकसान के साथ मलबे में गाय और बछड़ों के दबने का भी उल्लेख किया गया है। पशुओं की मौत और क्षति की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को भी बिना मानवीय दृष्टिकोण अपनाए ध्वस्त कर दिया गया। उनका कहना था कि यदि प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक भी थी, तो उसे बरसात के बीच गरीब परिवारों को बेघर कर नहीं किया जाना चाहिए था।

17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू रिमांड पर रामगोपाल अग्रवाल

शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग घोटालों में पूछताछ तेज

विश्व केसरी

रायपुर (संवाददाता)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग मामलों में आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामगोपाल अग्रवाल को गुरुवार को विशेष अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुमित कपूर ने उन्हें 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की रिमांड पर भेज दिया। अब इस अवधि में जांच एजेंसी उनसे विभिन्न मामलों में विस्तृत पूछताछ करेगी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईओडब्ल्यू रामगोपाल अग्रवाल को दोबारा विशेष अदालत में पेश करेगी। इसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। रामगोपाल अग्रवाल को बुधवार को ईओडब्ल्यू ने

हिरासत में लिया था। वे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व नान अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग से जुड़े मामलों में नाम सामने आने के बाद वे पिछले करीब तीन वर्षों से फरार थे। उनकी तलाश ईओडब्ल्यू के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा था। कस्टम मिलिंग मामले में जारी समन के बाद मंगलवार को ईओडब्ल्यू ने उनके बेटे वैभव अग्रवाल से लंबी पूछताछ की थी। इसके अगले दिन रामगोपाल अग्रवाल स्वयं ईओडब्लू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया।

EOW और ED की जांच के अनुसार, कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि के वितरण में कथित अनियमितताओं से लगभग 127 करोड़ रुपये, कोल लेवी मामले में कथित अवैध वसूली से करीब 540 करोड़ रुपये तथा शराब घोटाले में कथित सिंडिकेट के जरिए लगभग 3,200 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। हालांकि इन सभी मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है तथा आरोपों पर अंतिम न्यायिक निर्णय अभी आना शेष है। रिमांड के दौरान EOW इन तीनों मामलों में रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ कर साक्ष्यों और अन्य आरोपियों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करेगी।

शिकायतें, सीमांकन और आश्वासन नही हटी शासकीय भूमि से अतिक्रमण

विश्व केसरी

जांजगीर। अकलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम दर्रीटांड़ में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई महीनों से शिकायत और आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि इस दौरान अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है।

ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने कई बार तहसील कार्यालय और संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। प्रशासन की ओर से हर बार कार्रवाई का आश्वासन और नई तारीख दी जाती रही, लेकिन मौके पर अतिक्रमण

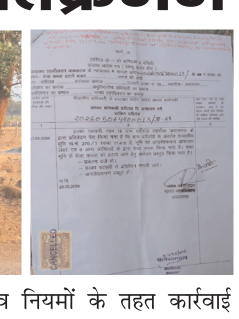

हटाने की कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी। इससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बढ़ रहे हैं और शासकीय भूमि पर कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण सरकारी जमीन पर कब्जे का दायरा बढ़ रहा है और भविष्य में इसे हटाना और भी मुश्किल हो सकता है। इधर, मामले को लेकर यदि कहीं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो राजस्व नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।'

अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि मौके पर अतिक्रमण हटाने की ठोस कार्रवाई ही उनकी समस्या का समाधान कर सकती है।

'ग्राम दर्रीटांड़ में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी प्राप्त की जाएगी। पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
– **अविनाश चौहान,** तहसीलदार अकलतरा

संपादकीय

जीएसटी से अर्थव्यवस्था में आया बड़ा बदलाव, राजस्व में भी वृद्धि

इंद्र शेखर शाह

विपक्ष विशेषकर कांग्रेस भले ही इसको गब्बर सिंह टैक्स कहे लेकिन हकीकत यह है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा एकीकृत, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है और अब यह देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ साबित हो रहा है।

जीएसटी से न सिर्फ सरकार के राजस्व में वृद्धि है बल्कि बाजार का एकीकरण हुआ है और अनुपालनों को बेहतर बनाने में मदद मिली है। जीएसटी 2.0 के साथ अब यह जीएसटी 3.0 के तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है यहां इसे ओर सरल बनाने के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के उपयोग और पूर्ण समावेश पर जोर होगा।

जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और एक जुलाई 2026 को इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह भारत की सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक रहा है, जिसने 'एक देश, एक कर' का सपना हकीकत बना दिया। जीएसटी से पहले देश के सभी राज्यों में अलग अलग अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था थी लेकिन जीएसटी ने पहले की जटिल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था (17 अलग-अलग टैक्स और 13 सेस) को एकीकृत कर दिया। जीएसटी से एक राष्ट्र, एक बाजार की अवधारणा को मजबूत किया और राज्य स्तर पर चेकपोस्ट और अलग-अलग टैक्स नियम खत्म हुए। माल और सेवाओं की आवाजाही आसान और सस्ती हुई, लॉजिस्टिक्स में सुधार आया।

जीएसटी से अप्रत्यक्ष करदाता आधार में भी भारी वृद्धि हुई है। 2017 में लगभग 66.5 लाख रजिस्टर्ड करदाता थे, जो मई 2026 तक 1.65 करोड़ हो गए। इस तरह में 140 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इससे अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण बढ़ा है। जीएसटी के लागू होने के बाद से राजस्व में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हई है। वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी के जुलाई में लागू होने के बाद मार्च 2018 तक कुल राजस्व संग्रह 7.4 लाख करोड़ रुपए रहा था जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गई है। औसत मासिक संग्रह दोगुने से अधिक हो गया। 2026-27 की शुरुआत में भी मजबूत आंकड़े आ रहे हैं।

जीएसटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया है ताकि राजस्व की हानि को रोक जा सके और राजस्व में वृद्धि हो। इसके साथ ही करदाता आधार बढ़ने ऐप भी जोर दिया जा रहा है। ई-वे बिल, ई-इनवॉइसिंग, एआई आधारित कंप्लायंस, जीएसटीएन पोर्टल आदि से टैक्स चोरी कम होने के साथ ही प्रक्रिया सरल हुई है और भौतिक संपर्क घटा है।

कैस्केडिंग इफेक्ट (टैक्स ऑन टैक्स) में कमी आई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवस्था से लागत कम हुई, जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद रही। जीएसटी के माध्यम से सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा दिया गया है। जीएसटी परीक्षा के जरिए केंद्र और राज्य मिलकर फैसले लेते हैं।

जीएसटी परिषद की 2025 में हई 56वीं बैठक के बाद इसमें अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर डिगा ओर जीएसटी 2.0 सितंबर 2025 से लागू हुए, जो 9 वर्षों की उपलब्धियों को और आगे ले गए। इसके तहत दरों को युक्तिकरण किया गया है जिसमें जीएसटी दरों के चार स्लैब को कम कर तीन कर दिया गया है लेकिन आम लोगों के लिय दो ही स्लैब अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रह गया है। 12 प्रतिशत वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है और 28 स्लैब ज्यादातर खत्म हो गया है। लग्जरी और सिन गुड्स (तंबाकू, हाई-एंड कारें आदि) पर 40 प्रतिशत दर प्रभावी है।

इसके साथ ही आम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से जरूरी वस्तुओं/सेवाओं पर दरें कम की गई है और बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से छूट दी गई है।

जीएसटी 2.0 के तहत दरों के युक्तिकरण से राजस्व का कुछ नुकसान हुआ है लेकिन इसका असर अल्पकालिक पड़ा है। बढ़ी हुई खपत, व्यापक टैक्स बेस और कम चोरी से यह संतुलित हुआ है। लग्जरी/सिन गुड्स पर 40प्रतिशत दर से राजस्व संतुलन बनाने में मदद मिली। कुल मिलाकर, जीएसटी 2.0 सरल अनुपालन, आम लोगों पर करों के कम बोझ और विकास पर फोकस करता है।

जीएसटी 2.0 ने शॉर्ट-टर्म राजस्व दबाव डाला लेकिन खपत और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर लंबी अवधि में राजस्व को सपोर्ट किया। 2026-27 में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि मांग का पूरा प्रभाव दिखेगा। 22 सितंबर 2025 से लागू जीएसटी 2.0 के बाद राजस्व संग्रह में मिश्रित लेकिन सकारात्मक बदलाव आए हैं। दरों में कटौती के बावजूद उपभोग बढ़ने, अनुपालन सुधरने और टैक्स बेस विस्तार से कुल संग्रह में वृद्धि बनी रही, हालांकि शुरुआती महीनों में कुछ धीमी वृद्धि देखा गया।

वित्त वर्ष 2025-26 में कुल जीएसटी संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपए रहा जो इससे लीछले वित्त वर्ष में संग्रहित राशि से लगभग 8.3 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में शुद्ध जीएसटी संग्रह 19.35 लाख करोड़ रुपए रहा जो इससे लीछले वित्त वर्ष के तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है। यह कोविड प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 के बाद सबसे कम वार्षिक वृद्धि रही, लेकिन दरों में कमी के बावजूद सकारात्मक रही। जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर मई 2026 तक 1.65 करोड़ हो गई। यह अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक व्यवसायों के कर व्यवस्था से औपचारिक रूप से जुड़ने की ओर संकेत देता है। 2017-18 में सकल जीएसटी संग्रह लगभग 7.4 लाख करोड़ रुपये था और पिछले कुछ वर्षों में इसमें लगातार वृद्धि हुई है।

पिछले पांच वर्षों में, कर संग्रह 2021-22 में 13.76 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 22.27 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह गति 2026-27 में भी जारी रही है। अप्रैल-जून 2026 के दौरान जीएसटी संग्रह लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच जो समझौते हुए हैं उससे रक्षा-सुरक्षा का पूरा परिदृश्य ही बदल जायेगा

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में द्विपक्षीय साझेदारी की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने संबंधी कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया। मोदी और अल्बनीज की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने सुरक्षा पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त घोषणा, ऊर्जा संबंधों पर संयुक्त बयान और साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के लिए एक खाका जारी किया। हम आपको बता दें कि असैन्य परमाणु ऊर्जा से जुड़े समझौते के जरिए ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की वाणिज्यिक आपूर्ति का रास्ता खुलेगा। इससे भारत की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को मदद मिलेगी। सरकारीएजेंसियां

साथ ही दोनों पक्षों ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के साथ-साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते पर भी तेजी से काम करने का निर्णय लिया। दोनों पक्ष महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर भी मिलकर काम करेंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने बढ़ते सहयोग का उल्लेख करते हुए स्वतंत्र एवं स्थिर हिंद-प्रशांत के महत्व पर जोर दिया। हम आपको बता दें कि रक्षा संबंधों को मजबूत करने की ये नयी पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अपनी सैन्य ताकत दिखाए जाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच की गई हैं।

हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सामने आईं उनकी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की आत्मीयता से भरी तस्वीरें केवल दो नेताओं की व्यक्तिगत मित्रता का प्रदर्शन नहीं थीं, बल्कि दोनों देशों के लगातार मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का सशक्त संदेश भी थीं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री सहित ऑस्ट्रेलिया के अनेक वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख हस्तियों से प्रधानमंत्री मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकातों ने यह भी साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी स्वीकार्यता और प्रभाव लगातार बढ़ा है। देखा जाये तो मोदी और अल्बनीज के बीच विकसित हुई यह मजबूत व्यक्तिगत समझ अब दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा और नई गति दे रही है। इसी भरोसे और राजनीतिक सामंजस्य का परिणाम रहा कि मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने ऐसे ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर लगाई, जिन्होंने विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा सहयोग को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया। नई संयुक्त रक्षा और सुरक्षा घोषणा के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और शक्ति संतुलन के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगियों के रूप में उभर रहे हैं। भारतखबर

देखा जाये तो नई रक्षा और सुरक्षा घोषणा बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में साझा रणनीतिक सोच का स्पष्ट संकेत है। इसके तहत दोनों देशों ने अपनी सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, संयुक्त सैन्य अभ्यासों की जटिलता

और आवृत्ति बढ़ाने, सूचनाओं के आदान प्रदान, सैन्य क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योगों के एकीकरण, रक्षा अनुसंधान, आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग को नई गति देने पर सहमति बनाई है। यह समझौता इस बात का प्रमाण है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अब दीर्घकालिक सामरिक साझेदार बन चुके हैं।

दोनों देशों के बीच विशेष महत्व का विषय समुद्री सुरक्षा सहयोग है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग रूपरेखा को अंतिम रूप देकर हिंद महासागर और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा निगरानी, परिचालन समन्वय, क्षमता निर्माण और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा कमान के बीच हुए समझौते से समुद्री कानून प्रवर्तन, सीमा सुरक्षा तथा समुद्री अपराधों पर संयुक्त कार्रवाई को नई मजबूती मिलेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है।

रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ऑस्ट्रेलियाई रक्षा महाविद्यालय में भारतीय सैन्य प्रशिक्षक की नियुक्ति का निर्णय है। यह केवल प्रशिक्षण का विषय नहीं, बल्कि दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच दीर्घकालिक विश्वास, पेशेवर सामंजस्य और रणनीतिक समझ को और गहरा करने वाला कदम माना जा रहा है। साथ ही रक्षा विज्ञान, रक्षा नवाचार, स्टार्टअप, रक्षा सामग्री तथा सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग का विस्तार दोनों देशों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाएगा।

इस यात्रा की दूसरी बड़ी उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा और असैनिक परमाणु सहयोग को नई गति देना रही। दोनों देशों ने वर्ष 2014 के असैनिक परमाणु समझौते को पूरी तरह लागू करने की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। इसके बाद शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा इस बात का संकेत है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को साझा रणनीति के साथ पूरा करना चाहते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, स्वच्छ ऊर्जा, जैव ईंधन, हरित ऊर्जा और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने पर दोनों देशों की सहमति भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

साथ ही महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने नई साझेदारी की शुरुआत की है। नई साझेदारी के पांच प्रमुख स्तंभों में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मजबूती और रक्षा अनुसंधान को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य केवल दोनों देशों की तकनीकी क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल व्यवस्था का निर्माण भी है। इससे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक प्रौद्योगिकी में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। इतिहास

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने पर भी सहमति जताई। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, खनन, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल अर्थव्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण, विमानन और आधुनिक उद्योगों में व्यापक अवसरों का उल्लेख किया। दोनों देशों ने माना कि भारत की विशाल बाजार क्षमता और ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नई संभावनाएं पैदा कर सकती हैं।

शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। बेंगलुरु में फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय तथा गुरुग्राम में विक्टोरिया विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने की प्रक्रिया को स्वीकृति मिली। भुवनेश्वर में खनन और खनन उपकरण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान, पारंपरिक ज्ञान, फिल्म निर्माण, विश्वविद्यालय सहयोग तथा कौशल विकास से जुड़े अनेक समझौते दोनों देशों के बीच जन संपर्क को और मजबूत करेंगे।

शिक्षा और जागरूकता से ही थमेगा जनसंख्या का ज्वार

योगेश कुमार गोयल

जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को 'विश्व जनसंख्या दिवस' मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो तेजी से बढ़ती आबादी के कारण ही हम सभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पहुंचाने में पिछड़ रहे हैं। बढ़ती आबादी की वजह से ही देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल हो चुकी है। हालांकि विगत दशकों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार जुटाने के कार्यक्रम चलाए गए लेकिन बढ़ती आबादी के कारण ये सभी कार्यक्रम 'ऊंट के मुंह में जीरा' ही साबित हुए। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही देश में आबादी और संसाधनों के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। वास्तविकता यही है कि विगत दशकों में देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ी, उस गति से कोई भी सरकार जनता के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की व्यवस्था करने में सफल हो ही नहीं सकती थी।

आज देश की बहुत बड़ी आबादी निम्न स्तर का जीवन जीने को विवश है। देश में करीब 40 प्रतिशत आबादी आजादी के बाद से ही गरीबी के आलम में जी रही है। गरीबी में जीवन गुजार रहे ऐसे बहुत से लोगों की यही सोच रही है कि उनके यहां जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ही ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे किन्तु यह सोच वास्तविकता के धरातल से परे है। लगातार बढ़ती महंगाई के जमाने में परिवार बड़ा होने से कमाने वाले हाथ ज्यादा होने पर जितनी आय बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरतें और विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना सामर्थ्य से परे हो जाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए सर्वाधिक जरूरी यही है कि घोर निर्धनता में जी रहे ऐसे लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के महत्व के बारे में जागरूक करने की ओर खास ध्यान दिया जाए क्योंकि जब तक इस कार्यक्रम में इन लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

देश में जनसंख्या वृद्धि का मुकाबला करने के लिए पिछले काफी समय से कुछ कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है लेकिन इस दिशा में कुछ राज्य सरकारें दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी नौकरी तथा स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी से अयोग्य अघोषित करने जैसे जिस तरह के उपायों पर विचार कर रही हैं, उन्हें तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। हालांकि जनसंख्या वृद्धि मौजूदा समय में गंभीर चुनौती है लेकिन ऐसे उपायों को संवैधानिक नजरिये से भी तर्कसम्मत नहीं माना जाता। चीन में 1980 से पहले केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, जिसका उल्लंघन करने पर दम्पति को न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता था बल्कि सजा भी दी जाती थी लेकिन वहां यह नीति सफल नहीं हुई। इसीलिए चीन सरकार ने 2016 में इस नीति में बदलाव कर दो बच्चों की अनुमति दी और बाद में तीन बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। चीन की तानाशाही सरकार द्वारा नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए दम्पत्तियों को तीन बच्चे करने की अनुमति क्यों दी गई, इसके कारण समझना भी जरूरी है। दरअसल वहां लोगों की सामान्य प्रजनन दर में निरन्तर गिरावट आ रही है और कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक यही स्थिति भारत में भी होनी है।

जनसंख्या में स्थायित्व और कामकाजी युवाओं की स्थिर संख्या के लिए महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए और चीन में यह दर निरन्तर गिर रही है। 1970 में चीन में यह दर 5.8 थी, जो 2015 में घटकर 1.6 और 2020 में केवल 1.3 ही रह गई जबकि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ती गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (एनबीएस) के अनुसार आने वाले समय में आबादी में अधिक उम्र वालों की संख्या बढ़ने से संतुलित विकास और जनसंख्या को लेकर दबाव बढ़ेगा।

बोध कथा

नि:स्वार्थ रूप से की गईं सेवाएं एक दिन अवश्य फल्लवित होती हैं

नर्स के रूप में हम तीन डायमंड विभूतियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहला महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं। महात्मा गांधी के जीवन को जब हमने पढ़ा कि गांधीजी कैसे बड़े हुए, उनके जीवन में कौन-कौन सी धारणाएं थीं। उनके जीवन का बचपन से लेकर बड़े होने तक, बचपन में चोरी, मांस खाया और उसके पश्चाताप तक सबकुछ जो उन्होंने किया। कैसे एक-एक भूल को उन्होंने सुधारा, कैसे वो आगे बढ़े और कैसे इस देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व बने। साबरमती का संत तथा राष्ट्रपिता जिसे आज कहते हैं। कैसे इस व्यक्ति ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने जीवन की भूलों को ठीक करते हुए आगे बढ़ते हुए कहां से कहां पहुंच गए।

दूसरा हमारे समाज में पालना और सेवा का एक अभिप्राय शब्द नर्स भी है जिसे अंग्रेजी वर्ण में तोड़ कर व्याख्या किया जाए तो सुंदर अर्थ निकलता है। एन से नोबिल्टी अर्थात् चरित्र की महानता, यू से अप-टू-डेट अर्थात् अपने ज्ञान में संपूर्ण जागरूक, आर से रेस्पॉन्स, एस से स्किलफुल ज्ञान केवल थ्योरी का नहीं लेकिन प्रैक्टिकल और इ से एमपिथि अर्थात् केवल सहानुभूति नहीं समानुभूति। नर्सेज आंदोलन की शुरुआत करने वाली महिला फ्लोरेंस नाइटेंगल इंग्लैंड में जन्मी थीं। ये महिला 1820 ई. में एक उच्च घराने में पैदा हुई थी। वह कैसे इतनी बड़ी व्यक्तित्व हुईं? उस जमाने में नर्स के प्रोफेशन को इतनी मान्यता नहीं थी। लोग इसे ऊंचा प्रोफेशन नहीं समझते थे। मरीजों की हालत उस समय बहुत खराब रहती थी। कभी कपड़े नहीं बदले जाते तो कभी बेड की चादर नहीं बदली जाती थी, चारों तरफ गंदगी रहती थी। उस समय घर का विरोध सहन करते हुए इस महिला ने फैसला किया कि मुझे नर्स बनना है।

तीर तेवर — सागर कुमार

व्यंग्य केसरी

कौन हूँ मैं, बूझो तो जानूँ!

अशोक मतवाला

मैं भारत में पैदा हुआ। जिला पटियाला के कस्बे नाभा की मिट्टी में पहला कदम रखा। नारायणगढ़, जिला अंबाला, की गलियों में धूल फांकी, रोहतक में बड़ा हुआ, चंडीगढ़ में पढ़ा-लिखा और वहीं पत्रकारिता की रोटियाँ सेंकी। 'द ट्रिब्यून' में दशक भर नौकरी की, पहली सफल यूनियन का संस्थापक अध्यक्ष बना। मेरी नाल भारत की धरती में गड़ी है, मेरी यादें भारत की हवाओं में उड़ती हैं, मेरे पुरखे भारत की मिट्टी में सो रहे हैं।

लेकिन ठहरिए...अगर कोई पूछ बैठे— 'साबित करो कि तुम कौन हो?' तो मैं जेब टटोलता हूँ।

ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं।

वोटर आईडी? नहीं।

आधार? नहीं।

पैन? नहीं।

राशन कार्ड? नहीं।

पासपोर्ट? वह भी नहीं।

अब सरकारी बाबू मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे मैं मंगल ग्रह से पैराशूट लेकर उतरा हूँ।

मैं कहता हूँ, 'भाई, मेरा पूरा खानदान भारत में है।' वह कहता है, 'फाइल में कहाँ है?' मैं कहता हूँ, 'गाँव वाले पहचानते हैं।' वह कहता है, 'सिस्टम नहीं पहचानता।'

मैं कहता हूँ, 'मैंने ट्रिब्यून में काम किया है।'

वह मुस्कुराकर कहता है, 'लेकिन पोर्टल पर आपका रिकॉर्ड नहीं खुल रहा।'

यही तो आधुनिक भारत का चमत्कार है। पहले आदमी पैदा होता था, फिर कागज़ बनते थे। अब पहले कागज़ चाहिए, तभी आदमी होने का भरोसा मिलता है।

व्यंग्य यह नहीं कि मेरे पास दस्तावेज़ नहीं हैं। व्यंग्य यह है कि मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ एक खाली कॉलम— 'कृपया वैध दस्तावेज़ संलग्न करें।'

आज की व्यवस्था में यादों का कोई कॉलम नहीं है। न माँ की गोद का, न स्कूल की हाज़िरी का, न पड़ोसियों की गवाही का।

और मज़ेदार बात यह है कि हाल के सार्वजनिक विमर्श में यह भी दोहराया गया कि आधार, वोटर आईडी, पैन या पासपोर्ट अपने-आप में नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं हैं। भारत में नागरिकता एक कानूनी स्थिति है, जिसे संविधान और नागरिकता कानून के अनुसार तथ्यों से स्थापित किया जाता है; कोई एक सार्वभौमिक 'नागरिकता कार्ड' सभी नागरिकों को जारी नहीं किया जाता।

तो फिर मैं कौन हूँ? विदेश में लोग कहते हैं— 'इंडियन।' भारत में कोई पूछे— 'प्रमाण?' मैं कहूँ— 'बचपन, भाषा, मिट्टी, रिश्ते, यादें... 'वह कहे— 'क्षस्त्र अपलोड कीजिए।'

लगता है अब जन्म लेने से ज़्यादा ज़रूरी है, जन्म का स्कैन संभालकर रखना।

मैं न फिरंगी हूँ, न बंजारा। मैं उस पीढ़ी का प्रतिनिधि हूँ जिसकी पहचान कागज़ों से कम, जीवन से ज़्यादा बनी थी। लेकिन डिजिटल युग ने जीवन से ज़्यादा फ़ाइलों पर भरोसा करना सीख लिया है।

आखि़र में मुझे अपने ही देश से यही पूछने का मन करता है— 'अगर मेरी मिट्टी, मेरी भाषा, मेरी स्मृतियाँ, मेरा श्रम, मेरा इतिहास और मेरे अपने भी मेरी पहचान नहीं हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? और अगर मैं नहीं जानता, तो शायद सिस्टम भी नहीं जानता। 'शायद भविष्य का सबसे बड़ा परिचय यही होगा— 'आदमी बाद में, दस्तावेज़ पहले। हिंदू होने के नाते मेरा यह हक है मुझे अपने भारत की मिट्टी में ही मिट्टी होने दिया जाए। मेरे वसीयत-नामें भी यही दर्ज है! भगवान न करे मुझे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ही.....।

इतिहास

9 जुलाई का दिन कई प्रमुख घटनाओं, आविष्कारों और उपलब्धियों के लिए दर्ज है । 1981 में आज ही के दिन प्रसिद्ध गेम Donkey Kong रिलीज़ हुआ था, जिसमें पहली बार मारियो का किरदार दुनिया के सामने आया था । 2011 में आज के दिन South Sudan दुनिया का सबसे युवा देश बना था ।आज की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं:1540: इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII ने अपनी चौथी पत्नी ऐन ऑफ क्लीव्स से विवाह रद्द कर दिया।1877: लंदन में दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित Wimbledon Championship की शुरुआत हुई ।1962: प्रसिद्ध पॉप-आर्ट कलाकार एंडी वारहोल की मशहूर पेंटिंग 'कैंपबेल सूप कैन्स' (CampbellÓs Soup Cans) का लॉस एंजिल्स में पहली बार प्रदर्शन हुआ ।1991: 30 सालों के रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में दोबारा शामिल किया गया।

पहली बारिश के साथ लजीज सरई पुटू-बोड़ा की धमक छत्तीसगढ़ के बाज़ार में

सीजन में अकेले बस्तर के लोग 5 से 7 लाख रु.की बोड़ा चट कर जाते है

विश्व केसरी

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। छत्तीसगढ़ के वनांचल में हुई पहली बारिश और उमस के कारण साल वृक्षों के नीचे उगने वाले 'सरई पुटू, बोड़ा तथा मशरूम' बिलासपुर से बस्तर तक के बाज़ारों में बिकने के लिए पहुंच चुकी है, प्रारम्भ होने के चलते भाव कुछ तेज है।

ग्रामीण अंचलों में जंगल में जाकर आदिवासी ग्रामीण जन 'सरई पुटू 'मशरूम' तथा 'बोड़ा' एकत्र करने में जुट गए हैं, सरई पुटू को बस्तर में लोग बोड़ा कहते है। सरई पुटू अथवा 'बोड़ा' की पहली खेप छत्तीसगढ़ के बाज़ार में आना प्रारंभ हो गया हैं। दाम पूछो मत छत्तीसगढ़ में सामान्यत: 200 ग्राम वाली 'सोली बोड़ा' का दाम 400 रु के आसपास चल रहा है। इस लिहाज से बाज़ार की सबसे महंगी सब्जी 'बोड़ा' का रेट 2000 रु प्रतिकिलो तक महानगरों में बिका करती है। बेलगहना के पत्रकार सुमन पांडे का कहना है कि बेलगहना वनांचल में निवासरत लोग बोड़ा का स्वाद न जाना तो क्या खाया अक्सर ये सवांद बाज़ार में सुनाई दे जाता है।

'बोड़ा' के स्वाद के सौकीन बताते है कि इसके इतने अधिक दाम देने की वजह है, इसकी पैदावार खेत बाड़ी में नही की जा सकती, 'बोड़ा' कुदरत की नेमत हैं । दो चार दिनों की बारिश के बाद जब चटक धूप होती है तब 'बोड़ा' की खुदाई साल के पेड़ों के नीचे की जाती हैं। शुरुआत दौर का 'बोड़ा' नरम छिलके और लज़ीज़ गुदे की वजह से काफी महंगा होता है पूरे सीजन में बोड़ा की दर 400 रु. किलो से नीचे नही जाती ।हांलाकि अभी बिलासपुर के बाजार में बोड़ा 600 रु. किलो की दर पर बिक रहा है। 'बोड़ा' के जगदलपुर के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पाढ़ी का कहना है कि मौसमी ब्यापार का अनुमान लगाने वाले बताते हैं कि अकेले बस्तर के बाजार में ही लोग 5 से 7 लाख रु का 'बोड़ा' चट कर जाते हैं। बताते हैं कि 'बोड़ा' उत्पादन के लिए साल वनों का होना जरूरी है। इस लिहाज से बस्तर , कांकेर, कोंडागांव, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, अम्बिकापुर जशपुर, रायगढ़ और बिलासपुर के बेलगहना, कोटा के साल जंगलों से अबाध तरीके से बाजारों में पहुँचना प्रारम्भ हो गया है। वहीं इससे ठीक उलट सागौन वनों वाले दक्षिण बस्तर में इसकी पैदावार वहां की शून्य है।

उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और खनिज तत्व सहित औषधि लाभ देने वाले 'बोड़ा' के जायके के दीवाने शाकाहारी -मांसाहारी दोनों होते है। कोई खेड़ा भाजी के साथ कि रेसिपी पसंद करता है तो कोई चिकन के साथ। बेचने वाले बताते है जंगल में मिलने वाले दूसरे मशरूमों के खाने में विषले होने का खतरा रहता है, पर 'बोड़ा' की दोनों किस्मे , 'जात बोड़ा' और 'राखड़ी बोड़ा' बेहिचक खाई जा सकती है।

बस्तर के मांचकोट ,तिरिया इलाके से बड़ी मात्रा में बोड़ा लेकर ग्रामीण खासी आय अर्जित कर रहे है। पैली, सोली ,टोकने, बोरे जहां कहीं 'बोड़ा' लिए ग्रामीण नजर आते हैं। कोचिए इन पर बाज की तरह झपट पड़ते हैं। प्रकृति के अलावा अन्य किसी तरीके से बोड़ा का उत्पादन असंभव होने से इसके बेहतर दाम मिल जाते हैं।

तीन हिरणों की मौत, बारनवापारा में वन्यजीव की सुरक्षा पर सवाल

विश्व केसरी

बलौदाबाजार (भुवन लाल)। जिले के बार नवापारा अभयारण्य में लगातार दो दिनों के भीतर तीन हिरणों की मौत ने वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संरक्षित क्षेत्र में एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने वन विभाग की निगरानी, गश्त और सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। ताजा मामला सेला क्षेत्र का है, जहां बुधवार को एक हिरण मृत अवस्था में मिला। प्रारंभिक तौर पर आवारा कुत्तों के हमले की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वन विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होने की बात कह रहा है।

जानकारी के अनुसार, हिरण का शव मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृत हिरण के शरीर पर मिले चोट के निशानों के आधार पर कुत्तों के हमले की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि यदि संरक्षित अभयारण्य के भीतर आवारा कुत्ते आसानी से प्रवेश कर वन्यजीवों का शिकार कर रहे हैं, तो वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस काम की है। इससे पहले मंगलवार को भी इसी क्षेत्र में दो हिरणों की मौत हुई थी। उस समय वन विभाग ने दावा किया था कि दोनों हिरणों की मौत आपसी संघर्ष के कारण हुई है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन एक और हिरण की मौत ने विभाग के दावों पर संदेह खड़ा कर दिया है। आखिर दो दिनों में लगातार तीन हिरणों की मौत केवल संयोग है या अभयारण्य की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक?

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभयारण्य में यदि हिरण लगातार असामयिक मौत का शिकार हो रहे हैं, तो यह केवल एक सामान्य घटना नहीं बल्कि संरक्षण व्यवस्था की विफलता का संकेत माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभयारण्य क्षेत्र में नियमित निगरानी और प्रभावी गश्त नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। यदि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो बाहरी खतरे अभयारण्य के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाते। विशेषज्ञों का मानना है कि हिरण जैसे वन्यजीव पहले से ही प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में यदि संरक्षित क्षेत्र के भीतर भी उनकी जान सुरक्षित नहीं है, तो यह वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। लगातार हो रही मौतों से काले हिरण सहित अन्य वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। वन विभाग फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रहा है, लेकिन लगातार तीन मौतों के बाद अब केवल रिपोर्ट का इंतजार पर्याप्त नहीं माना जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि अभयारण्य में सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए, नियमित गश्त बढ़ाई जाए, आवारा कुत्तों की समस्या पर तत्काल नियंत्रण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी भी वन्यजीव की जान इस प्रकार न जाए। दो दिनों में तीन हिरणों की मौत ने बार नवापारा अभयारण्य की सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी है। अब लोगों की निगाह इस बात पर टिकी है कि वन विभाग इस मामले को केवल औपचारिक जांच तक सीमित रखता है या फिर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम भी उठाता है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संरक्षित अभयारण्य में वन्यजीवों की सुरक्षा केवल कागजों तक सिमटकर रह जाएगी।

कबीरधाम में फल-फूल रहा झोलाछाप डॉक्टरों का साम्राज्य, गरीबों की जिंदगी पर खुला खिलवाड़

विश्व केसरी

कवर्धा (जगदंबिका साहू)। कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य विभाग की कथित निष्क्रियता और ढीले रवैये के कारण झोलाछाप डॉक्टरों का अवैध कारोबार लगातार फैलता जा रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तक बिना किसी वैध डिग्री और पंजीकरण के दर्जनों अवैध क्लिनिक खुलेआम संचालित हो रहे हैं। इन तथाकथित डॉक्टरों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नजर आती है। परिणामस्वरूप गरीब, आदिवासी और ग्रामीण मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है।

जिले के चिल्फी, झलमला, कुई, कुकदूर, पोलमी, रेंगाखार, तरेगांव, दलदली सहित अनेक वनांचल क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। इसके अलावा कवर्धा जिला मुख्यालय, पंडरिया, बोड़ला, सहसपुर लोहारा तथा अन्य कस्बों और गांवों में भी बिना किसी वैध अनुमति के क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। इन क्लिनिकों में मरीजों की जांच, इंजेक्शन, ग्लूकोज चढ़ाना, दवाइयां देना और गंभीर बीमारियों का इलाज तक किया जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि जिले के पंडरिया और बोड़ला विकासखंड के कई वनांचल क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी पर्याप्त नहीं हैं। कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दूर हैं, डॉक्टरों की कमी बनी रहती है और लोगों को उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर झोलाछाप डॉक्टरों ने पूरे इलाके में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया है। कई स्थानों पर तो गांव-गांव इलाज का ठेका लेकर मरीजों का उपचार किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

सूत्रों के अनुसार इन अवैध क्लिनिकों में कई बार प्रतिबंधित अथवा बिना अनुमति वाली दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है। मरीजों को बीमारी की सही जांच किए बिना एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड और भारी मात्रा में इंजेक्शन लगाए जाने की शिकायतें भी समय-समय पर उठती रही हैं। इससे मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने का खतरा बना रहता है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई दिखाई नहीं देती। जिले में जब भी नए कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या अन्य वरिष्ठ अधिकारी पदभार संभालते हैं, शुरुआती दिनों में कुछ क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई कर सील करने जैसी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कुछ समय बाद पूरा अभियान ठंडे बस्ते में चला जाता है और वही झोलाछाप डॉक्टर फिर से अपने क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज शुरू कर देते हैं। इससे यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि कार्रवाई केवल औपचारिकता निभाने तक सीमित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला मुख्यालय के मिनीमाता चौक, लोहारा नाका चौक, बिजली ऑफिस क्षेत्र, बस स्टैंड सहित कई प्रमुख स्थानों पर खुलेआम अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। ऐसे स्थानों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग की नजर इन पर नहीं पड़ती। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब ये क्लिनिक सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम संचालित हो रहे हैं तो आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीम इन्हें देखने से कैसे चूक जाती है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विकसित किया अभिनव 'रेन वाटर इन्ग्रेस टेस्ट बेंच'

विश्व केसरी

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कोचिंग डिपो ने नवाचार, संरक्षा एवं यात्री सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए रेल कोचों में वर्षा जल के रिसाव (रैन वाटर इंग्रेस) की जांच के लिए स्वदेशी 'रेन वाटर इन्ग्रेस टेस्ट बेंच' विकसित किया है। इस अभिनव प्रणाली के माध्यम से कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिसियल रैन सिमुलेशन) का वातावरण तैयार कर कोचों की छत, खिड़कियों, साइड पैनलों तथा अन्य संवेदनशील जोड़ों से होने वाले संभावित जल रिसाव की प्रभावी जांच एवं समय रहते उसका निराकरण किया जा सकेगा।

अब तक वर्षा जल के रिसाव की पहचान मुख्यत: प्राकृतिक बारिश पर निर्भर रहती थी, जिसके कारण वर्षभर इसकी जांच संभव नहीं हो पाती थी। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर कोचिंग डिपो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए अधिकांशत: स्क्रैप सामग्री से इस टेस्ट बेंच का डिजाइन एवं निर्माण किया। केवल कुछ आवश्यक पुर्जों की ही बाजार से खरीद की गई, जिससे यह प्रणाली अत्यंत किफायती एवं संसाधन-सक्षम सिद्ध हुई है।

यह अभिनव टेस्ट बेंच वर्षभर कृत्रिम वर्षा परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कोचों में छिपे हुए जल रिसाव की समय रहते पहचान कर उसे सेवा में शामिल करने से पहले ही दूर किया जा सकता है। इससे मानसून के दौरान यात्रियों को जल रिसाव जैसी असुविधाओं से राहत मिलेगी, कोचों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा बार-बार होने वाले रखरखाव की आवश्यकता भी कम होगी। इसकी पोर्टेबल डिजाइन के कारण इसका उपयोग पारंपरिक कोचों के साथ-साथ आधुनिक वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के कोचों में भी किया जा सकता है। यह स्वदेशी नवाचार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पहल न केवल कोच अनुरक्षण की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, बल्कि यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक एवं बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेष रूप से मानसून के दौरान वर्षा जल रिसाव से संबंधित शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

नशे में धुत ठेकेदार ने मॉल की सीढ़ियों पर चढ़ाई कार, वाहन जब्त चालक हिरासत में

विश्व केसरी

कोरबा (बबलू श्रीवास)। कोरबा के पाम मॉल में देर रात एक कथित ठेकेदार ने नशे की हालत में अपनी स्कॉर्पियो मॉल की सीढ़ियों पर चढ़वा दी। घटना रात करीब 1:15 बजे की है। सुरक्षा सुपरवाइजर की शिकायत पर पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार, बिलासपुर निवासी कथित ठेकेदार रमन सिंह अपने दो साथियों के साथ रात करीब 1 बजे ONC बार में शराब पीने गया था। बार से निकलने के बाद वह मॉल के बाहर पहुंचा, जहां उसकी सफेद स्कॉर्पियो (CG 10 CD 0513) खड़ी थी। आरोप है कि नशे की हालत में रमन सिंह ने चालक को स्कॉर्पियो मॉल के अंदर ले जाने के लिए कहा। चालक ने वाहन को सीधे मॉल के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। मौके पर मौजूद गार्ड और अन्य लोगों ने विरोध किया, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी गई। सुरक्षा कर्मियों से भी हुई बहस प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर रमन सिंह उनसे उलझ गया। वह चालक को बार-बार सीढ़ियों पर गाड़ी चढ़ाने के लिए कहता रहा। पूरी घटना मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ONC बार निर्धारित समय के बाद भी खुला रहता है। उनका कहना है कि नियमों के उल्लंघन और देर रात तक शराब परोसने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों ने आबकारी विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि पाम मॉल के सुरक्षा सुपरवाइजर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

पुटु निकालने गए ग्रामीण की जंगल में दर्दनाक मौत

विश्व केसरी

कोरबा (बबलू श्रीवास)। कोरबा वनमंडल के करतला वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पीडिया के तुर्रीकटरा जंगल में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुटु (जंगली मशरूम) संग्रह करने जंगल गए एक ग्रामीण की जंगली हाथी के हमले में मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल में जाने से पहले विशेष सावधानी बरतने और हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर जंगल में प्रवेश नहीं करने की अपील की है। जानकारी के अनुसार, ग्राम पीडिया निवासी जहाज़ सिंह राठिया (करीब 55 वर्ष) गुरुवार सुबह पुटु निकालने के लिए तुर्रीकटरा जंगल पहुंचे थे। इसी दौरान उनका सामना एक जंगली हाथी से हो गया। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार हाथी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद नियमानुसार आगे की कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एसईसीएल की पांच खदानों को मिला 5-स्टार दर्जा, उत्कृष्ट खनन का राष्ट्रीय सम्मान

विश्व केसरी

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने उत्कृष्ट एवं उत्तरदायी खनन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग में अपनी पाँच खदानों को 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की है।

बंगवार भूमिगत खदान (सोहागपुर क्षेत्र), खैराहा भूमिगत खदान (सोहागपुर क्षेत्र), बेहराबांध भूमिगत खदान (जोहिला क्षेत्र), विजय वेस्ट भूमिगत खदान (हसदेव क्षेत्र) तथा जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना (भटगांव क्षेत्र) को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। किसी एक मूल्यांकन वर्ष में एसईसीएल की पाँच खदानों को एक साथ 5-स्टार रेटिंग मिलना कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। कोयला मंत्रालय की स्टार रेटिंग प्रणाली देश की कोयला एवं लिग्नाइट खदानों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन करती है। इसके अंतर्गत सुरक्षित एवं वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण, भूमि पुनर्वास, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण, वैधानिक अनुपालन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा परिचालन दक्षता जैसे विभिन्न मानकों पर खदानों का आकलन किया जाता है। इन सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खदानों को ही सर्वोच्च 5-स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है।

इस वर्ष 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली एसईसीएल की बंगवार, खैराहा, बेहराबांध एवं विजय वेस्ट भूमिगत खदानों ने सुरक्षित संचालन, वैज्ञानिक खनन, उत्पादन दक्षता, श्रमिक कल्याण तथा पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना, जो इस वर्ष 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली एसईसीएल की एकमात्र ओपनकास्ट परियोजना है, ने ओवरबर्डन प्रबंधन, हरित विकास, जल संरक्षण एवं सुरक्षित उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। इस उपलब्धि पर एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन ने कहा, 'एसईसीएल की पाँच खदानों को एक साथ 5-स्टार रेटिंग मिलना पूरे एसईसीएल परिवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यह उपलब्धि हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यावसायिक सहयोगियों एवं सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का परिणाम है। सुरक्षित, सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल खनन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। आधुनिक तकनीकों और श्रेष्ठ खनन पद्धतियों को अपनाते हुए हम परिचालन उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर स्थापित है आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम

विश्व केसरी

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। मानसून के दौरान रेलवे पुलों पर नदियों के जलस्तर की सतत एवं सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम को अपनाया गया है। सेंसर आधारित यह अत्याधुनिक प्रणाली वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर स्थापित की गई है। यह प्रणाली 24 घंटे रियल-टाइम में जलस्तर की निगरानी करते हुए संरक्षित एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पूर्व में नदियों के जलस्तर का आकलन पारंपरिक मीटर गेज प्रणाली के माध्यम से किया जाता था, जिसमें मैनुअल रीडिंग लेने के कारण सूचना प्राप्त होने में विलंब तथा त्रुटि की संभावना बनी रहती थी। अचानक जलस्तर बढ़ने की स्थिति में समय पर जानकारी उपलब्ध न होने से रेलवे ट्रैक एवं पुलों की संरक्षा का त्वरित आकलन करना चुनौतीपूर्ण होता था।

इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। यह प्रणाली सेंसर आधारित तकनीक के माध्यम से पुलों पर लगे जलस्तर संकेतकों की निरंतर निगरानी करती है तथा ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से एकीकृत रहती है। जैसे ही नदी का जलस्तर पूर्व निर्धारित चेतावनी अथवा खतरे के स्तर तक पहुँचता है अथवा उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, सिस्टम स्वत: संबंधित अधिकारियों एवं अभियंताओं के मोबाइल फोन पर तत्काल एसएमएस अलर्ट भेज देता है। इससे आवश्यक सुरक्षा उपाय समय रहते लागू किए जा सकते हैं तथा रेल परिचालन को संरक्षित बनाए रखने में सहायता मिलती है।

इस प्रणाली में संबंधित सहायक मंडल अभियंता, रेल पथ निरीक्षक (पीडबल्यूआई) सहित अन्य अधिकृत अधिकारियों के मोबाइल नंबर पंजीकृत रहते हैं। परिणामस्वरूप जलस्तर में होने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुँच जाती है, जिससे त्वरित निर्णय लेने और आवश्यक कार्रवाई करने में सुविधा होती है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जिन 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, वे निम्नानुसार हैं—

1. झारसुगुड़ा-ईब स्टेशनों के मध्य ईब नदी पर रेलवे पुल क्रमांक 184 अप।
2. ईब-ब्रजराजनगर स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 182 अप।
3. भूपदेवपुर-राबर्ट्सन स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 86 अप।
4. कोरबा-गेवरा रोड स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 63 डाउन।
5. नैला-चांपा स्टेशनों के मध्य हसदेव नदी पर रेलवे पुल क्रमांक 46 डाउन।
6. जयरामनगर-अकलतरा स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 12 मिडिल।
7. दगौरी-निपनिया स्टेशनों के मध्य शिवनाथ नदी पर रेलवे पुल क्रमांक 462 मिडिल।
8. रसमड़ा-दुर्ग स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 348 डाउन।
9. मुंडीकोटा-तुमसर स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 116 अप इत्यादि शामिल हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अपनाई गई यह आधुनिक तकनीक मानसून के दौरान रेलवे पुलों एवं ट्रैक की संरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ संभावित बाढ़ जैसी परिस्थितियों में समय पर चेतावनी उपलब्ध कराकर संरक्षित, विश्वसनीय एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है।

कोरबा में सड़क निर्माण पर कलेक्टर पैदल पहुंचकर किया निरीक्षण

विश्व केसरी

कोरबा (बबलू श्रीवास)। जिले में सड़क अधोसंरचना को बेहतर बनाने और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बुधवार को निर्माणाधीन सड़कों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ध्यानचंद चौक से रूमगरा होते हुए बालको के बजरंग चौक तथा रिसदा चौक से रिसदी चौक तक सड़क निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। हर 15 दिन में मरम्मत के निर्देश दिए।

हाल ही में हुई बारिश से प्रभावित सड़क के हिस्सों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य पूरा होने तक सड़क की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि हर 15 दिन में आवश्यक मरम्मत कर आवागमन सुचारु रखा जाए, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष जोर

कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 5.74 किलोमीटर लंबी टू-लेन सीसी सड़क का निर्माण तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ढेंगुरनाला-बेलगिरी पुल का भी किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ढेंगुरनाला-बेलगिरी पुल का भी जायजा लिया। उन्होंने पुल की मरम्मत, प्रस्तावित रपटा निर्माण और वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जल्द विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके।

भारी गिरावट से उबरा बाजार, सेंसेक्स 238 अंक चढ़कर बंद; निफ्टी 24,000 के करीब

विश्व केसरी

मुंबई । पिछले दिन की भारी गिरावट से उबरते हुए भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के सत्र में बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 0.30 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली।

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 238.22 अंक यानी 0.31 प्रतिशत बढ़कर 76,741.82 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी50 80.75 अंक या 0.34 प्रतिशत बढ़कर 23,962.80 पर पहुंच गया।

दिन के सत्र में सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,503.60 से 72.53 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 76,576.14 पर खुला और दिन के कारोबार में यह 823.04 अंकों यानी 1.07 प्रतिशत की उछाल के साथ 77,326.65 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

वहीं, निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 23,882.05 से 0.19 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 23,928.95 पर खुला और दिन के कारोबार में यह 252.65 अंकों यानी 1.05 प्रतिशत की उछाल के साथ 24,134.70 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान, लगभग 2,793 शेयरों में तेजी, 1,263 शेयरों में गिरावट और 167 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.38 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन काफी हद तक सकारात्मक रहा, अधिकांश सूचकांकों में खरीदारी देखी गई। निफ्टी रियल्टी शीर्ष लाभ कमाने वाला सूचकांक बनकर उभरा, जिसमें 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके बाद निफ्टी मीडिया (2 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (1.6 प्रतिशत) और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (1.6 प्रतिशत) का स्थान रहा।

दूसरी ओर, निफ्टी आईटी में 0.47 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी ऑटो में 0.25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी 50 में, सन फार्मा 2.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में उभरी, उसके बाद भारती एयरटेल (2.4 प्रतिशत), बजाज फिनसर्व (2.3 प्रतिशत), इंडिगो (2 प्रतिशत), इटरनल (2 प्रतिशत) और ग्रासिम तथा कोटक महिंद्रा बैंक (1.9 प्रतिशत) के शेयरों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई।

ऑस्ट्रेलियनसुपर के 500 मिलियन एयू डॉलर के निवेश पर वित्त मंत्री ने जताई खुशी, पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

विश्व केसरी

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियनसुपर की ओर से गुरुवार को भारत में 500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुशी जताई और देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पीएम मोदी की पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, 'भारत में ज्यादा निवेश को बढ़ावा देने और एनआईआईएफ को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। उनके नेतृत्व में, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एनआईआईएफ पर अपना भरोसा बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलियनसुपर का धन्यवाद।'

ऑस्ट्रेलियनसुपर की ओर से भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता से फंड का भारत की सभी एसेट क्लास में निवेश बढ़कर 3.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो गया है।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'भारत, ऑस्ट्रेलियनसुपर की ओर से 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का स्वागत करता है। इस निवेश की घोषणा आज सुबह मेलबर्न में कंपनी के सीईओ पॉल श्रोडर ने की। यह भारत की विकास और सुधार की दिशा में वैश्विक भरोसे का एक और उदाहरण है। साथ ही, यह हमारी गतिशील अर्थव्यवस्था द्वारा वैश्विक निवेशकों को मिलने वाले अपार अवसरों को भी दर्शाता है।'

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए ऑस्ट्रेलियनसुपर के सीईओ पॉल श्रोडर ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घकालिक सोच और व्यापार एवं निवेश के बारे में उनकी समझ ने देश में निवेशकों के विश्वास को मजबूत किया है।

मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से सोना फिसला, चांदी 2.23 लाख रुपए के नीचे

विश्व केसरी

मुंबई । मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिला है और दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब आधा प्रतिशत कम हो गया है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,43,711 रुपए के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 1,43,451 रुपए पर खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में ही इसमें और बिकवाली देखी गई।

सुबह 10 बजे, यह 490 रुपए या 0.34 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,43,221 रुपए पर था। अब तक के कारोबार में सोने ने 1,43,101 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,43,511 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

सोने के साथ चांदी में भी तेज गिरावट देखी गई है। चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,23,437 रुपए के मुकाबले 1,437 रुपए की कमजोरी के साथ 2,22,000 रुपए पर खुला।

फिलहाल यह 1,321 रुपए या 0.59 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,22,116 रुपए पर था।

अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,21,502 रुपए का न्यूनतम स्तर और 2,22,761 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोना 0.26 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,071 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58 डॉलर प्रति औंस पर था।

सोने और चांदी में गिरावट की वजह अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव को माना जा रहा है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हवाई हमला किया।

वहीं, ईरान ने मध्य पूर्व में अन्य देशों जैसे बहरीन और कुवैत पर हमला कर दिया है। इससे पूरे क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्व हो गई है।

इस घटनाक्रम से अन्य अहम कमोडिटी कच्चे तेल में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है। ब्रेंचमार्क ब्रेंट क्रूड एक प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ करीब 79 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब बना हुआ है।

मध्यपूर्व संकट से कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत : आईएमएफ

विश्व केसरी

वॉशिंगटन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक संस्था ने भारत की 2026 की ग्रोथ का अनुमान थोड़ा घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगले साल ऊर्जा से जुड़ी दिक्कतों के कम होने पर देश की ग्रोथ और तेज होगी।

आईएमएफ ने अपने ताजा 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में 2026 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान अप्रैल के अनुमान से 0.1 प्रतिशत अंक घटा दिया, लेकिन 2027 के लिए अनुमान 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया।

आईएमएफ का कहना है कि उम्मीद से बेहतर आर्थिक गतिविधि और मजबूत घरेलू मांग देश के आउटलुक को सहारा दे रही है।

आईएमएफ अधिकारियों ने अपनी ताजा 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि भारत ने कई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ग्लोबल अनिश्चितता का बेहतर ढंग से सामना किया है, हालांकि मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव की वजह से ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस साल विकास दर पर असर डालेंगी।

आईएमएफ रिसर्च विभाग की प्रमुख डेनिज इगन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों को बताया, 'भारत के लिए, हमने इस साल के अनुमान को बहुत मामूली रूप से 0.1 प्रतिशत अंक घटाकर 6.4 कर दिया है। और अगले साल, यानी 2027 के लिए विकास दर के अनुमान को 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया है। इगन ने कहा, 'अच्छी बात यह है कि हाल के डेटा में नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। साथ ही, अप्रैल तक के हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर भी दिखाते हैं कि कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों में काफी मजबूती बनी हुई है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि इस साल ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने इस सकारात्मक गति के असर को खत्म कर दिया है। हालांकि,आईएफएफ को उम्मीद है कि अगले साल ये दबाव कम हो जाएंगे।

इगन ने कहा, '2027 की ओर बढ़ते हुए, हमें उम्मीद है कि भारत की ग्रोथ और मजबूत होगी क्योंकि एनर्जी शॉक का असर कम हो जाएगा और मीडियम-टर्म ग्रोथ लगभग 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

भारत के लिए यह नया अनुमान तब आया है जब आईएमएफ ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान 3 प्रतिशत और 2027 के लिए 3.4 प्रतिशत पर लगभग वैसा ही बनाए रखा है।

वित्त वर्ष 27 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा शामिल: रिपोर्ट

विश्व केसरी

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, नीतिगत उपायों और सेवाओं के मजबूत निर्यात के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2027 के लिए उसका संशोधित वृद्धि दर अनुमान, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) के 6.4 प्रतिशत के हालिया अनुमान से अधिक है।

एडीबी ने कहा, 'विकास दर को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए पॉलिसी में बदलाव, ईंधन कर में कटौती, खास तौर पर टारगेटेड क्रेडिट सपोर्ट, मजबूत सर्विस निर्यात और पब्लिक कैपिटल खर्च से बढ़ावा मिलेगा।'

एडीबी ने भारत के लिए वित्त वर्ष 28 की ग्रोथ का अनुमान भी 7.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जो अप्रैल के अनुमान जैसा ही है।

एडीबी ने कहा कि मध्यम अवधि का आउटलुक बेहतर होते ग्लोबल हालात और अलग-अलग पार्टनर देशों के साथ व्यापार समझौतों से मिली एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस से समर्थित है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एनर्जी की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से वित्त वर्ष 27 की ग्रोथ के अनुमान में कमी की गई, क्योंकि इनसे लोगों की असली आय कम होती है और उपभोक्ता खर्च पर असर पड़ता है।

बैंक चेतावनी दी कि भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और मौसम की वजह से खेती में कमजोरी के कारण आउटलुक पर जोखिम अभी भी नीचे की ओर झुका हुआ है।

एडीबी ने वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की महंगाई दर का अनुमान भी बदलकर 5.2 प्रतिशत कर दिया, जबकि वित्त वर्ष 28 के लिए महंगाई दर का अनुमान 4 प्रतिशत पर ही बनाए रखा।

एडीबी ने दक्षिण एशिया के लिए 2026 में विकास दर का अनुमान पहले के 6.3 प्रतिशत से घटाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया है। इसके पीछे तेल की ऊंची कीमतें, माल ढुलाई की बढ़ती लागत और रेमिटेंस (विदेश से भेजी जाने वाली रकम) के प्रवाह को लेकर अनिश्चितता जैसे कारण बताए गए हैं।

विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए, बैंक ने 2026 के विकास दर अनुमान को 5.1 प्रतिशत से घटाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया है। बैंक का कहना है कि पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति और सप्लाई चेन को बाधित किया है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी है और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी हुई है।

भारत में दुनिया की आधी जीसीसी मौजूद, एंटरप्राइस एआई टैलेंट के दूसरे सबसे बड़े हब के रूप में रहा उभर : सीईए

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भारत में दुनिया के करीब आधे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) मौजूद हैं और देश एंटरप्राइस एआई टैलेंट के दूसरे सबसे बड़े हब के रूप में उभर रहा है। यह इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और हाई-वैल्यू ग्लोबल ऑपरेशन में देश की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है। यह बयान मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को दिया।

राष्ट्रीय राजधानी में सीआईआई जीसीसी बिजनेस समिट में नागेश्वरन ने कहा कि भारत का जीसीसी इकोसिस्टम बीते दो दशकों में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरा है। इसमें बैक-ऑफिस से 2,000 से अधिक सेंटर तक का बड़ा बदलाव शामिल है, जिसमें आज 20 लाख से ज्यादा पेशेवरों को रोजगार मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में रोजगार अब 23 लाख के करीब पहुंच रहा है, जबकि सालाना आय 60 अरब डॉलर से अधिक हो गई है और 100 अरब डॉलर के करीब पहुंचने की राह पर है।

नागेश्वरन ने कहा, 'दुनिया के लगभग आधे जीसीसी अब भारत में हैं। यह अचानक नहीं हुआ। यह हमारे लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि टैलेंट ही सबसे अहम चीज है।

उन्होंने बताया, 'ये सेंटर पहले लागत कम रखने के लिए भारत आए थे, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से यहीं टिके रहे।'

सीईए ने कहा कि जीसीसी अब भारत की जीडीपी में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देते हैं और भारत के बड़े शहरों में बनने वाली नई ऑफिस स्पेस में इनका बड़ा हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि भारत के पैमाने के आस-पास भी कोई दूसरा देश नहीं है, क्योंकि दुनिया के लगभग आधे जीसीसी अब यहीं से काम कर रहे हैं।

इस सेक्टर के विकास के बारे में बताते हुए नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय जीसीसी अब कम लागत में बैक-ऑफिस सपोर्ट देने वाली अपनी पारंपरिक भूमिका से कहीं आगे निकल चुके हैं। आज वे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में हाई-वैल्यू वाले काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल बैंक मुंबई और बेंगलुरु से रिस्क सिस्टम और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मैनेज करते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां चेन्नई और पुणे से गाड़ियों और एम्बेडेड सिस्टम की डिजाइन तैयार करती हैं।

सरकार इंस्टाग्राम नोटिस मामले में मेटा के जवाब की समीक्षा के बाद उठाएगी अगला कदम : आईटी सचिव

विश्व केसरी

नई दिल्ली। सरकार इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के जरिए कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट (सीएसईएएम) को बढ़ावा देने को लेकर जारी नोटिस पर मेटा के औपचारिक जवाब की समीक्षा करने के बाद कंपनी के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। यह जानकारी आईटी सचिव एस.कृष्णन ने गुरुवार को दी।

सीआईआई जीसीसी बिजनेस समिट के दौरान कृष्णन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नोटिस को लेकर मेटा के औपचारिक जवाब का इंतजार कर रहा है, ताकि आगे की कार्रवाई के बारे में कोई फैसला लिया जा सके।

कृष्णन ने कहा, 'हम उस नोटिस के औपचारिक जवाब का इंतजार करेंगे जो हमने जारी किया है और उसके बाद जवाब के आधार पर कोई फैसला लेंगे।'

बीते शनिवार को सरकार ने मेटा को एक नोटिस जारी किया था। यह नोटिस इंस्टाग्राम पर उन पेड विज्ञापनों को लेकर चिंताएं सामने आने के बाद जारी किया गया, जिनसे कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (सीएसईएएम) को बढ़ावा मिलने और उस तक पहुंच आसान होने की बात कही गई थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को निर्देश दिया कि वह ऐसी सामग्री से जुड़े सभी विज्ञापनों और कंटेंट को हटा दे।

इससे पहले, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे मेटा को बुलाएं और इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट होने के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगें। मंत्रालय ने इस समस्या से निपटने के लिए सोशल मीडिया कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी थी।

नोटिस मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर, मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट किया।

कंपनी ने बच्चों के शोषण को एक 'भयानक अपराध' बताया और कहा कि वह आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए बड़े पैमाने पर लागू किए जाने वाले उपायों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित डिटेक्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल करती है।

मेटा ने यह भी कहा कि वह टेक्नोलॉजी में निवेश जारी रखेगी, अपने विज्ञापन रिव्यू प्रोसेस को मजबूत करेगी और युवा यूजर्स की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाएगी।

कूड़े के ढेर से बना हरियाली का स्वर्ग! नोएडा का यह पार्क जल संरक्षण की मिसाल, खरगोश भी हैं आकर्षण

नोएडा के सेक्टर-54 में स्थित 'वेस्ट टू वेल्थ-वेटलैंड पार्क' शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है. कभी कचरे का ढेर रही यह जगह आज हरियाली, प्राकृतिक जल शोधन, जल संरक्षण और जैव विविधता के लिए जानी जाती है. 'खरगोश पार्क' के नाम से मशहूर यह स्थान अब स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है.

नोएडा के सेक्टर-54 में स्थित 'वेस्ट टू वेल्थ-वेटलैंड पार्क' इस बात की मिसाल है कि सही योजना और प्रयास से किसी भी जगह को नया स्वरूप दिया जा सकता है. जो स्थान कभी कूड़े के ढेर के रूप में जाना जाता था, वह आज हरियाली, जल संरक्षण और प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र बन चुका है. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह पार्क एक प्रेरणादायक पहल माना जा रहा है.

करीब 25 एकड़ में फैला यह वेटलैंड पार्क पहले बेकार पड़ी जमीन और कचरे का क्षेत्र था. अब यहां हरियाली, स्वच्छ वातावरण और जल संरक्षण की आधुनिक व्यवस्था देखने को मिलती है. यह बदलाव दर्शाता है कि बेहतर योजना और प्रयासों से शहरों में पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक स्थान विकसित किए जा सकते हैं.

इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत इसका प्राकृतिक जल शोधन तंत्र है. यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से आने वाले पानी को वेटलैंड तकनीक के जरिए प्राकृतिक रूप से साफ किया जाता है. शुद्ध होने के बाद इस पानी को बड़े तालाबों में संग्रहित किया जाता है, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ पानी का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होता है.

वेटलैंड पार्क में प्राकृतिक रूप से साफ किए गए पानी को तालाबों में संग्रहित किया जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है. तेजी से शहरीकरण के दौर में जल संरक्षण की यह पहल भविष्य की जरूरतों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

यह पार्क 'खरगोश पार्क' के नाम से भी जाना जाता है. जल संरक्षण के साथ-साथ यह स्थानीय लोगों के लिए खुली हवा में समय बिताने और प्रकृति के बीच सुकून पाने की बेहतरीन जगह बन चुका है. हरियाली, तालाब और प्राकृतिक वातावरण शहर की भागदौड़ से राहत का एहसास कराते हैं, इसलिए सुबह और शाम यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं.

सेक्टर-54 स्थित यह वेटलैंड पार्क पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के बीच संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है. यहां जल संरक्षण, हरियाली और प्राकृतिक पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों के लिए एक आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक स्थान भी विकसित किया गया है.

'वेस्ट टू वेल्थ-वेटलैंड पार्क' इस बात का उदाहरण है कि जल संरक्षण केवल बड़े बांधों या विशाल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है. शहरों के भीतर भी प्राकृतिक तकनीकों के माध्यम से पानी का संरक्षण और पर्यावरण सुधार की दिशा में प्रभावी पहल की जा सकती है. यह पार्क इसी सोच और सतत विकास का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया है.

नोएडा का यह पार्क शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बेहतर तालमेल का उदाहरण है. प्राकृतिक जल शोधन, तालाबों के निर्माण और हरियाली के कारण यह स्थान लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है. पार्क में खरगोशों के साथ कई अन्य छोटे जीव भी देखने को मिलते हैं।

तापसी पन्नू का फिटनेस चैलेंज : 60 मिनट में किए 275 बर्पीज, 200 सिट-अप्स और 150 पुश-अप्स

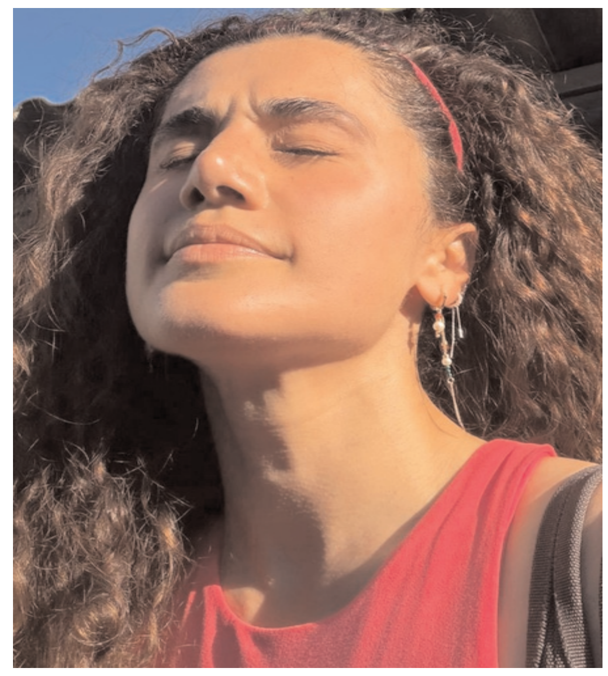

मुंबई । बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर अपने हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट की झलक शेयर की और बताया कि एक घंटे के कठिन एक्सरसाइज सेशन के बाद उनकी क्या हालत हुई।

तापसी पन्नू ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वर्कआउट के बाद की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके चेहरे पर थकान के साथ मेहनत की चमक भी दिखाई दे रही थी। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, '60 मिनट में 275 बर्पीज, 200 सिट-अप्स, 150 पुश-अप्स और 150 एयर स्क्वॉट्स करने के बाद मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं।'

तापसी इससे पहले भी अपने वर्कआउट अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रही हैं। 3 जून को उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उनकी पीठ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। इसके साथ उन्होंने लिखा था, 'इस कहानी की सीख यह है कि खुरदुरी जमीन पर बैक और कोर की एक्सरसाइज एक साथ मत कीजिए।'

वर्कफ्रंट की बात करें तो 38 वर्षीय तापसी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2010 में तेलुगु फिल्म झुम्मांडी नादम से की थी। हिंदी सिनेमा में उन्होंने 2013 में निर्देशक डेविड धवन की फिल्म चश्मे बद्दूर से डेब्यू किया था।

तापसी हाल ही में निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म 'अस्सी' में नजर आई थीं। यह एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा है, जो यौन उत्पीड़न के मामलों पर आधारित है। फिल्म में एक जांचकर्ता और बचाव पक्ष की टीम आंकड़ों के पीछे छिपे चौंकाने वाले सच और मानवीय दर्द को सामने लाने की कोशिश करती है।

अब तापसी जल्द ही नेटफ्लिक्स की फिल्म 'गांधारी' में दिखाई देंगी। फिल्म की कहानी एक ऐसी मां के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करती है। रहस्य और दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म में तापसी एक मजबूत और जुझारू मां के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में उनके साथ अभिनेता इश्वाक सिंह भी अहम भूमिका निभाएंगे।

तापसी बेबी, पिंक, मुल्क, द गाजी अटैक, मनमर्जियां, बदला, मिशन मंगल, सांड की आंख, थप्पड़, हसीन दिलरुबा, फिर आई हसीन दिलरुबा, रश्मि रॉकेट, डंकी और लूप लपेटा जैसी कई चर्चित फिल्मों में अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं।

निजी जीवन की बात करें तो तापसी पन्नू ने पूर्व डेनिश बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता मैथियास बोए से शादी की थी।

सिर्फ सजावट नहीं, सेहत का भी याल रखता है स्नेक प्लांट, जानिए फायदे

आजकल लोग अपने घरों और कार्यालयों को हरा-भरा और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के इनडोर पौधे लगाते हैं। इन्हीं में से एक है स्नेक प्लांट (संसेविएरिया), जो अपनी खूबसूरत लंबी पत्तियों के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी कई लाभों के लिए भी जाना जाता है। यह ऐसा पौधा है जो कम देखभाल में आसानी से बढ़ता है और घर के वातावरण को बेहतर बनाने में मदद करता है।

स्नेक प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हवा को शुद्ध करने में सहायक माना जाता है। यह वातावरण में मौजूद कुछ हानिकारक तत्वों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे प्रदूषकों के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि इसे घर, कार्यालय और अन्य इनडोर स्थानों के लिए एक लोकप्रिय पौधा माना जाता है।

इस पौधे की एक और खास बात यह है कि यह रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे नींद अच्छी आती है और हवा शुद्ध रहती है। यह हवा में मौजूद टॉक्सिन्स जैसे फार्मेल्डिहाइड, बेंजीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन को कम करता है। इसी वजह से कई लोग इसे बेडरूम में रखना पसंद करते हैं।

स्नेक प्लांट मानसिक सुकून देने में भी मददगार माना जाता है। घर या कार्यस्थल पर हरियाली का होना तनाव कम करने और सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक हो सकता है।

स्वस्थ जीवन के लिए हेल्दी लिवर जरूरी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 'सुरक्षा कवच' का महत्व

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को लिवर के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए बताया है कि स्वस्थ लिवर अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद है। शरीर के कई जरूरी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में लिवर की अहम भूमिका होती है। इसी कारण इसकी देखभाल करना और स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है।

मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे अपने लिवर की सेहत को गंभीरता से लें, क्योंकि एक स्वस्थ लिवर न केवल शरीर को बीमारियों से बचाता है, बल्कि बेहतर जीवनशैली और लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य का आधार भी बनता है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, लिवर शरीर का एक ऐसा अंग है, जो बिना रुके कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। यह न केवल शरीर को संक्रमण और विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है, बल्कि रक्त में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि लिवर को शरीर का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच माना जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, लिवर शरीर में मौजूद हानिकारक और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है। भोजन, दवाइयों और अन्य स्रोतों से शरीर में पहुंचने वाले कई तत्वों को यह फिल्टर करता है, जिससे शरीर के अन्य अंग सुरक्षित रहते हैं। यदि लिवर सही तरीके से काम न करे तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

इसके अलावा, लिवर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। संतुलित कोलेस्ट्रॉल हृदय और रक्त वाहिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है। लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर शरीर में वसा और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन भी बिगड़ सकता है।

पाचन प्रक्रिया में भी लिवर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह बाइल (पित्त) नामक द्रव का निर्माण करता है, जो भोजन में मौजूद वसा को पचाने और पोषक तत्वों को शरीर द्वारा अवशोषित करने में सहायता करता है। इसलिए स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए भी लिवर का स्वस्थ रहना आवश्यक है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी का सेवन और शराब तथा जंक फूड से दूरी बनाकर लिवर को स्वस्थ रखा जा सकता है। साथ ही समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है।

कैल्शियम-आयरन की खान है यह फल, दांत और हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद, चंपारण में होता है खूब

महुआ का फल कैल्शियम और आयरन का एक बेहतरीन सोर्स है. यह शरीर में खून की कमी को पूरा कर हड्डियों को मजबूत करता है. यदि किसी इंसान के दांत हिल रहे हों तो उसे महुआ के पेड़ की छाल का अर्क निकालकर उससे कुल्ला करना चाहिए. इससे...

आयरन, विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर 'महुआ' महिलाओं के लिए अमृत से कम नहीं है. वैसे तो यह बिहारके चंपारण जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में आसानी से दिख जाता है, लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व से सटे वनवर्ती इलाकों में इसकी भरमार है. गांव में रहने वाली ज्यादातर महिलाएं इसके फल, फूल और छाल का उपयोग वर्षों से करती आ रही हैं. जंगल से सटे बस्तियों में रहने वाले थारू और उरांव जनजाति के लोग इसे बड़ी ही खूबसूरती से इकट्ठा करते हैं. इसे घर लाकर पानी से साफ करते हैं और धूप में सुखाकर अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं.

ओरल समस्याओं के लिए छाल का उपयोग

करीब चार दशकों से आयुर्वेदाचार्य के रूप में कार्यरत बेतिया के भुवनेश पांडे बताते हैं कि महुआ एक सुपर फूड है, जिसे शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं. गांव में आज भी इन्हें इकट्ठा कर खीर, हलवा और पूढ़ी के रूप में सेवन किया जाता है. इतना ही नहीं, महुवा के पेड़ की छाल को दांत सहित अन्य सभी ओरल समस्याओं के उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है।

योग से जुड़े देश-संस्कृति और समुदायः वियतनाम, लाओस, मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान ने पढ़ा 'योग्य से सुयोग्य' बनने का पाठ

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर दुनिया भर में 'योग के माध्यम से स्वस्थ वृद्धावस्था' थीम के तहत बड़े उत्साह और व्यापक भागीदारी के साथ आयोजन किए गए। विभिन्न देशों में मौजूद दूतावास और उच्चायोग इस भव्य आयोजन से जुड़ी अहम जानकारी और तस्वीरें साझा कर रहे हैं।

वियतनाम में भारत के दूतावास, हनोई ने नेशनल वियतनाम बुद्धिस्ट संघ के सहयोग से 'तम चुक पगोडा' परिसर में एक भव्य योग सत्र का आयोजन किया। यह ऐतिहासिक परिसर अपनी 1000 वर्षों से अधिक पुरानी विरासत और विश्व के सबसे बड़े बौद्ध परिसरों में से एक के रूप में जाना जाता है। यहां स्थित न्गोक (पर्ल) पगोडा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे भारत और वियतनाम के इंजीनियरों ने मिलकर पत्थरों से निर्मित किया था, जो दोनों देशों के गहरे आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है। इस शांत और आध्यात्मिक वातावरण में सैकड़ों प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया और योग के माध्यम से शारीरिक स्फूर्ति एवं मानसिक संतुलन का अनुभव किया।

इसी क्रम में वियतनाम के क्वांग निन्ह प्रांत में भी भारत के दूतावास ने स्थानीय प्रशासन और योग फेडरेशनों के सहयोग से हजारों योग प्रेमियों के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हुए स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश दिया। आयोजकों ने प्रांतीय प्रशासन, योग संघों और सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

लाओस की राजधानी विएंतियाने में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने सामूहिक योग सत्र में भाग लिया। 'श्वास में एकता, गति में सामंजस्य और हर उम्र के लिए स्वास्थ्य' की भावना के साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने योग की सार्वभौमिकता और इसकी समग्र कल्याणकारी भूमिका को उजागर किया।

तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में उप स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उद्योग मंत्री श्री अजात ओवेजोव, भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य और भारत के मित्रों ने भी उत्साहपूर्वक योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर ने भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच सांस्कृतिक और जन-जन संबंधों को और मजबूत किया।

वहीं, मंगोलिया के उलानबातार में भारत के दूतावास और मंगोलियन योग फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति एन. एंखबयार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने योग को दैनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि जैप वैन हाइडर्न ने योग को शांति, स्वास्थ्य और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण बताया। मंगोलियन योग फेडरेशन की अध्यक्ष बी. तूल ने भारत सरकार और दूतावास के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं, ब्रह्माकुमारी संस्था की देश प्रतिनिधि इन्ना किम ने ध्यान की विधि का मार्गदर्शन किया।

योग विशेषज्ञों ने उच्च स्तरीय योगाभ्यास प्रदर्शित किया, जबकि भारतीय संस्कृति शिक्षक विवेक कुमार मधेशिया ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। भारतीय राजदूत ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग ने वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त की है और यह व्यक्ति को 'योग्य' से 'सुयोग्य' बनाता है।

‘सतलुज’ को ओटीटी से हटाए जाने पर नीरू बाजवा बोलीं, हमें साफ-साफ वजह पता चलनी चाहिए

मुंबई। पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने पर निराशा जाहिर की है। फिल्म को रिलीज होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही हटा दिया गया था।

- नीरू ने दिलजीत के साथ कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कहा कि दर्शकों को यह चुनने का हक है कि वे किसी फिल्म का समर्थन करना चाहते हैं या उसकी आलोचना करना चाहते हैं।
- उन्होंने आगे कहा कि दर्शकों को यह जानने का हक है कि फिल्म को अचानक ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्यों हटाया गया।

> मैंने ‘सतलुज’ देखी, भावनाएं निश्चित रूप से जागृत हुईं। एक फिल्म मनोरंजन से कहीं बढ़कर है। यह उसके निर्माताओं की आवाज, उनका जुनून, उनका सच और बरसों की कड़ी मेहनत है। किसी के पास भी बिना जवाबदेही के उसे दबाने की ताकत नहीं होनी चाहिए। लोग किसी फिल्म का समर्थन करें या उसकी आलोचना, यह उनका फैसला होना चाहिए। दर्शकों से यह विकल्प छीनना गलत है। हमें इसे देखने, खुद सोचने और यह तय करने का हक है कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है।

- अगर ‘सतलुज’ को हटाया गया है तो जनता को सच्चाई जानने का हक है। हमें स्पष्टीकरण चाहिए, खामोशी नहीं। पारदर्शिता कोई विशेषाधिकार नहीं है; यह एक जिम्मेदारी है।
- पंजाबी होने के नाते, हमें सवाल पूछने का हक है अगर हमारी मातृभूमि की कहानियों को हमसे छिपाया जाता है।

हम कुछ खास नहीं मांग रहे हैं। हम सच्चाई, निष्पक्षता और फिल्म को अनुभव करने और अपनी राय बनाने की आजादी मांग रहे हैं। हमारी आवाज मायने रखती है। हमारी कहानियां मायने रखती हैं और सच्चाई मायने रखती है।

राजीव खंडेलवाल ने ट्रांसजेंडर समुदाय से मांगी माफी, बोले-समाज की गलतियों पर मैं शर्मिंदा हूं

विश्व केसरी ■

मुंबई। अभिनेता राजीव खंडेलवाल अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। इस कड़ी में टीवी शो ‘तुम हो ना - घर की सुपरस्टार’ में उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर अपने विचार पेश किए और उनसे माफी मांगते हुए कहा कि समाज की ओर से हुई गलतियों पर वह शर्म से अपना सिर झुकाते हैं।

दरअसल, शो के एक एपिसोड में सोशल मीडिया स्टार पूजा शर्मा रेखा मेहमान बनकर पहुंचीं। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, समाज से मिले तिरस्कार और अपनी पहचान को स्वीकार करने की मुश्किल यात्रा के बारे में खुलकर बात की। उनकी कहानी सुनकर राजीव खंडेलवाल भावुक हो गए और उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया।

पूजा से बात करते हुए राजीव खंडेलवाल ने कहा, ‘आपने अपने भीतर जो ताकत पैदा की है, वह काबिल-ए-तारीफ है। आपके आसपास नकारात्मक सोच थी। लोगों ने आपका शोषण किया और आपको गलत समझा, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा। आपने हार नहीं मानी, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बन गईं। जिन लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उन सभी की ओर से मैं नेशनल टीवी पर शर्म से अपना सिर झुकाता हूं।‘

उन्होंने आगे कहा, ‘हममें से कई लोग ऐसी संवेदनशील बातों को समझ ही नहीं पाते। कई बार लोग गलत धारणाओं और डर के कारण ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। आज मैं उन सभी लोगों की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि बदलाव जरूर आएगा, भले ही उसमें समय लगे। मैं चाहता हूं कि आपके जैसे लोग आगे बढ़कर समाज को नई सोच दें। आपका अधिकार और सम्मान मिलें, जिसके आप हकदार हैं।‘

बातचीत के दौरान पूजा शर्मा रेखा ने बताया कि समाज में स्वीकार किए जाने का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था और कई बार उन्हें अकेले ही हर मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस पर राजीव ने कहा, ‘ ’देश में आज भी इस विषय को लेकर जागरूकता की कमी है।

जब किसी इंसान की बात सुनने वाला ही कोई न हो, तो उसका दर्द और भी बढ़ जाता है।

करण जौहर ने मनीष मल्होत्रा को दी बधाई, बोले- ‘आपने भारतीय फैशन को दुनिया के मंच पर नई पहचान दिलाई’

विश्व केसरी ■

मुंबई। फिल्ममेकर करण जौहर और मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दोस्ती काफी गहरी है। दोनों ने कई सालों तक साथ काम किया है। इस बीच करण ने मनीष मल्होत्रा के लंबे और शानदार सफर को याद करते हुए उनके लिए एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे मनीष ने सिर्फ फैशन की दुनिया में ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की सोच और अंदाज को भी बदलने का काम किया है।

करण जौहर ने गुरुवार को मनीष मल्होत्रा के लेटेस्ट फैशन शो का एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी दोस्ती के सफर को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पहली फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में साथ काम करने से दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हुआ।

करण ने लिखा, ‘ ’कुछ सफर सालों से नहीं, बल्कि सपनों से मापे जाते हैं और मनीष मल्होत्रा का सफर भी ऐसा ही है। मैं उनकी इस यात्रा का गवाह हूं और कई बार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला हूं।''

करण ने मनीष के शुरुआती करियर को याद करते हुए लिखा, ‘ ’साल 1990 में उन्होंने फिल्म ‘स्वर्ग’ से कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय सिनेमा में कपड़ों और किरदारों को पेश करने के अंदाज को बदल दिया। साल 1995 में मनीष ने फिल्म ‘रंगीला’ के लिए पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतकर कॉस्ट्यूम डिजाइन की दुनिया में एक नई पहचान बनाई।’ अपनी और मनीष की दोस्ती का जिक्र करते हुए करण ने कहा, ‘ ’हम दोनों की पहली साझेदारी फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ से हुई थी।

बिग बी ने फैंस को दी सलाह, गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें

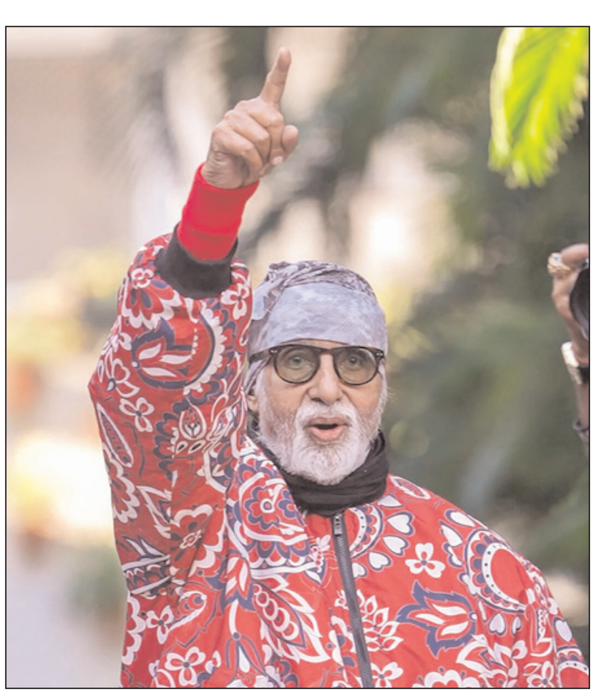

विश्व केसरी ■

मुंबई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने हालिया ब्लॉग के जरिए सीखने, आत्मचिंतन और जीवन में गलतियों को स्वीकार करने के महत्व पर बात की। अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि हर दिन एक नई सीख लेकर आता है और व्यक्ति को हमेशा नई चीजों को सीखने और खुद को बेहतर समझने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हर दिन काम की व्यस्तताओं के बाद बिग बी अपने फैंस (एक्सटेंडेड फैमिली) के नाम एक लंबा ब्लॉग लिखते हैं जिसमें उनके विचार, दिनभर के अनुभव और पुरानी यादें शामिल होती हैं।

अपने हालिया ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा, ‘हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। हर दिन नई सीख और नए अनुभव लेकर आता है। हर दिन उन नए मौकों के लिए खास होता है, जो हमें बदलाव को अपनाने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। सीखना सबसे बड़ी ताकत है। जो बातें हमें पहले नहीं पता थीं और जिन्हें केवल विशेषज्ञ जानते थे, उन्हें भी हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों के पास ज्ञान और अनुभव है, उनसे सीखते रहना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि खुद को समझने से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने लिखा, ‘आखिरकार सबसे ज्यादा मायने आपकी अपनी समझ, आपकी सोच और आपका अपना अनुभव रखता है। विशेषज्ञ भी गलतियां कर सकते हैं, फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं लेकिन जब आप अपने विवेक और अनुभव के आधार पर फैसला लेते हैं तो आपको अपने फैसलों पर बेहतर पकड़ होती है। अगर कोई गलती होती भी है, तो कम से कम यह संतोष रहता है कि वह आपकी अपनी गलती थी।

उन्होंने कहा कि गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण बात है।

उन्होंने लिखा, ‘अपनी गलती स्वीकार करना गलत नहीं है। बल्कि यह आपके व्यक्तित्व और चरित्र को दर्शाता है। एक बार जब आप अपनी गलती मान लेते हैं, तो उसकी वजह और उसके असर को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं ।

‘जूही मूई’ नहीं बनेगा सास-बहू ड्रामा, ईशा सिंह ने जताया भरोसा

विश्व केसरी ■

मुंबई। टीवी अभिनेत्री ईशा सिंह इन दिनों अपने नए शो ‘जूही मूई’ को लेकर चर्चा में हैं। शो में वह एक ऑटिस्टिक लड़की जूही सूरी का किरदार निभा रही हैं, जिसकी सोच और प्रतिभा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मीडिया से बात करते हुए ईशा ने कहा कि आज के दर्शक ऐसी कहानियां भी पसंद कर रहे हैं, जिनमें समाज से जुड़े मुद्दों को दिखाया जाता है। ईशा सिंह ने आईएएनएस से जब सवाल किया कि कई बार अलग सोच के साथ शुरू होने वाले शो बाद में सास-बहू ड्रामा में बदल जाते हैं। क्या ‘जूही मूई’ के साथ भी ऐसा होने की संभावना है, तो अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता।

ईशा ने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि इस शो के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी कहानी बाकी शोज से काफी अलग है। इस शो की पूरी कहानी एक खास विषय और अलग तरह के किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, इसलिए इसे सामान्य टीवी ड्रामे की तरह नहीं देखा जा सकता।‘

शो ‘जूही मूई’ में ईशा सिंह जूही सूरी नाम की एक होशियार और प्रतिभाशाली ऑटिस्टिक लड़की का किरदार निभा रही हैं। कहानी एक ऐसी युवती की है, जिसे समाज कई बार समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी अलग सोच और क्षमता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बनती है। मौजूदा कहानी में जूही अपने पिता को खोने के बाद मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसके पिता ही वह इंसान थे,

जिन्होंने हमेशा उसे दुनिया की परेशानियों से बचाया और उसका साथ दिया।

ईशा ने कहा, ‘टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है, जिसे बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। इसलिए कई बार चैनल और निर्माता दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कहानियां तैयार करते हैं। लंबे समय तक टीवी पर सास-बहू ड्रामा का दबदबा इसलिए रहा, क्योंकि दर्शक भी ऐसी कहानियों को काफी पसंद करते थे।‘

ईशा ने आगे कहा, ‘टेलीविजन पर अलग और गंभीर विषयों पर आधारित कहानियां बहुत कम देखने को मिलती रही हैं। करीब 16 साल पहले ऑटिज्म जैसे विषय पर एक शो आया था, लेकिन उसके बाद इस तरह के विषय को दोबारा प्रमुखता मिलने में काफी समय लग गया।

बॉलीवुड के संस्कारी ‘बाबूजी’ ने भी पर्दे पर कभी दिए थे बेहद बोल्ड सीन

विश्व केसरी ■

मुंबई। जब भी बॉलीवुड में संस्कारी पिता, प्यार करने वाले परिवार के मुखिया और आदर्शवादी ‘बाबूजी’ की बात होती है, तो सबसे पहले अभिनेता आलोक नाथ का नाम याद आता है। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक आलोक नाथ ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’ और ‘विवाह’ जैसी

फिल्मों में उनके पिता के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। आज जिन आलोक नाथ को दर्शक एक आदर्श पिता के रूप में देखते हैं, उन्होंने अपने शुरुआती दौर में रोमांटिक हीरो की भूमिका भी निभाई थी।

अपनी शांत, सादगी भरी और संस्कारी छवि के लिए मशहूर आलोक नाथ ने साल 1987 में आई फिल्म ‘कामाग्नि’ में एक अलग अंदाज दिखाया था। इस फिल्म में उन्होंने रोमांटिक किरदार निभाया था और अभिनेत्री टीना मुनीम (टीना अंबानी) के साथ नजर आए थे। फिल्म में उनके कुछ बोल्ड और रोमांटिक सीन की उस समय काफी चर्चा हुई थी। आलोक नाथ का जन्म 10 जुलाई 1956 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और मां गृहिणी थीं। उनके पिता चाहते थे कि आलोक भी उनकी तरह डॉक्टर बनें, लेकिन किस्मत ने उन्हें अभिनय की दुनिया में पहुंचा दिया।

औपचारिक स्वागत समारोह में झलकी भारत-ऑस्ट्रेलिया की गहरी रणनीतिक साझेदारी : विदेश मंत्रालय

विश्व केसरी

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की राजधानी मेलबर्न स्थित गवर्नमेंट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य और औपचारिक स्वागत किया गया। इस विशेष समारोह में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विक्टोरिया की गवर्नर मार्गरेट गार्डनर एसी भी उपस्थित रहीं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर भव्य स्वागत की तस्वीरों को साझा किया। पोस्ट में लिखा कि पारंपरिक सम्मान और औपचारिक स्वागत के साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते रणनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को एक बार फिर दुनिया के सामने प्रदर्शित किया।

समारोह के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया। ऑस्ट्रेलियाई सेना पीएम मोदी के सेरेमोनियल स्वागत के लिए एक लाइन में लगी और इस दौरान भारत का राष्ट्रगान गूंज

उठा।पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। भारत-ऑस्ट्रेलिया दोस्ती पर हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम के लिए पहुंचे अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। अल्बनीज ने पीएम मोदी का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने एक तस्वीर खिंचवाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छह दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे हैं। यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, निवेश, शिक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, खनिज संसाधन और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। दोनों देश स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी दोनों देशों का सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वहीं, विक्टोरिया राज्य भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। यहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और हजारों भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में विक्टोरिया और भारत के बीच लगातार सहयोग बढ़ रहा है।

नेपाल के स्पीकर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया काठमांडू आने का न्योता

विश्व केसरी

काठमांडू। भारत और नेपाल के बीच संसदीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। नेपाल के प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष डोल प्रसाद आर्यल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नेपाल यात्रा का निमंत्रण दिया है। नेपाल के स्पीकर सचिवालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

काठमांडू में नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव के साथ हुई शिष्टाचार मुलाकात के दौरान स्पीकर आर्यल ने ओम बिरला को नेपाल आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा अध्यक्ष की यात्रा से दोनों पड़ोसी देशों के बीच संसदीय संवाद और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बैठक के दौरान भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कहा, 'लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी नेपाल यात्रा के इच्छुक हैं। उन्होंने नेपाल के स्पीकर आर्यल और नेपाली सांसदों को भारत आने का निमंत्रण दिया, ताकि वे भारतीय संसदीय व्यवस्था और कार्यप्रणाली का अध्ययन कर सकें। हालांकि भारत और नेपाल के सांसदों के बीच नियमित रूप से यात्राएं होती रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों की संसदों के अध्यक्षों के बीच आधिकारिक यात्राएं सीमित रही हैं। ऐसे में यह पहल संसदीय कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बैठक में नेपाल के स्पीकर डोल प्रसाद आर्यल ने भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा दोनों देशों के रिश्ते साझा सभ्यता, भौगोलिक निकटता और गहरे सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, सुरक्षा, नागरिक उड्डयन, जल संसाधन, कनेक्टिविटी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंध लगातार विस्तार कर रहे हैं। आर्यल ने संसदीय कूटनीति को दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने जानकारी दी कि नेपाल में नई प्रतिनिधि सभा के गठन के बाद भारत-नेपाल संसदीय मैत्री समूह का गठन किया गया है। 10 सदस्यीय इस समूह का नेतृत्व सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद बिपिन आचार्य कर रहे हैं।

संक्षिप्त खबर

मध्यपूर्व संकट से कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत : आईएमएफ

विश्व केसरी

वॉशिंगटन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक संस्था ने भारत की 2026 की ग्रोथ का अनुमान थोड़ा घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगले साल ऊर्जा से जुड़ी दिक्कतों के कम होने पर देश की ग्रोथ और तेज होगी। आईएमएफ ने अपने ताजा 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में 2026 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान अप्रैल के अनुमान से 0.1 प्रतिशत अंक घटा दिया, लेकिन 2027 के लिए अनुमान 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया। आईएमएफ का कहना है कि उम्मीद से बेहतर आर्थिक गतिविधि और मजबूत घरेलू मांग देश के आउटलुक को सहारा दे रही है। आईएमएफ अधिकारियों ने अपनी ताजा 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि भारत ने कई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ग्लोबल अनिश्चितता का बेहतर ढंग से सामना किया है, हालांकि मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव की वजह से ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस साल विकास दर पर असर डालेंगी। आईएमएफ रिसर्च विभाग की प्रमुख डेनिज इगन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों को बताया, भारत के लिए, हमने इस साल के अनुमान को बहुत मामूली रूप से 0.1 प्रतिशत अंक घटाकर 6.4 कर दिया है। और अगले साल, यानी 2027 के लिए विकास दर के अनुमान को 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया है।

'पहले से अधिक जोरदार पलटवार करेंगे' : होर्मुज हमलों को लेकर जेडी वेंस ने ईरान को दी चेतावनी

विश्व केसरी

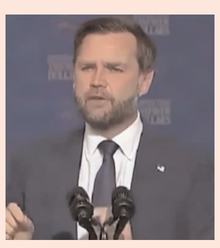

वाशिंगटन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आरोप लगाया है कि ईरान ने कमर्शियल जहाजों पर हमले फिर से शुरू करके अमेरिका के साथ हालिया समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री यातायात में बाधा डालने की कोई भी और कोशिश अमेरिका की ओर से और भी कड़े सैन्य जवाब को न्योता देगी। जेडी वेंस ने विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन हाल की दुश्मनी के बाद तेहरान के साथ एक समझौते पर पहुंच गया था, लेकिन ईरान ने उसका पालन नहीं किया। वेंस ने कहा, हमने ईरानियों के साथ एक समझौता किया था। यह समझौता उस समय हुआ जब अमेरिका अधिकतम दबाव और अधिकतम ताकत की स्थिति में था। वेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी वजह से ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो गई। उन्होंने कहा, हमारी शानदार अमेरिकी सेना और राष्ट्रपति की कोशिशों की वजह से हम इस स्थिति में अधिकतम ताकत के साथ पहुंचे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट हो गया, उसकी पारंपरिक सैन्य क्षमता भी खत्म हो गई। अब ईरान के कुछ लोग कह रहे हैं कि वे अमेरिका के साथ अपने संबंध बदलना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं।

न्यूयॉर्क से रवाना हुई आईएनएस सुदर्शिनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने लहराया तिरंगा

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की आईएनएस सुदर्शिनी ने अमेरिका में न्यूयॉर्क से आगे का सफर शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क में ठहरने के दौरान नौसेना के पोत ने न केवल भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक, सांस्कृतिक और जन-जन के संबंधों को भी नई मजबूती प्रदान की।

सुदर्शिनी स्वदेशी रूप से निर्मित तीन मस्तूल वाला बार्क पोत है। यह भारतीय नौसेना के 10 महीने लंबे अंतर महासागरीय अभियान 'लोकायन 2026' पर है। इस यात्रा के एक हिस्से के रूप में सुदर्शिनी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और सेल फोर्थ 250 समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह आयोजन दुनिया भर की नौसेनाओं और पारंपरिक नौकायन पोतों की भागीदारी के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। अब भारतीय नौसेना के नौकायन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शिनी ने 'लोकायन 2026' अभियान के तहत अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पर अपना सफल प्रवास पूरा कर लिया है। 8 जुलाई को न्यूयॉर्क से प्रस्थान के साथ ही इस ऐतिहासिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय संपन्न हुआ। न्यूयॉर्क प्रवास का सबसे यादगार क्षण वह रहा जब आईएनएस सुदर्शिनी ने भव्य परेड ऑफ सेल में हिस्सा लिया। इस दौरान पोत ने प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते हुए हडसन नदी में नौकायन किया। तिरंगे से सुसज्जित आईएनएस सुदर्शिनी अंतरराष्ट्रीय नौकायन पोतों और युद्धपोतों के विशाल बेड़े के साथ आगे बढ़ी। इसने भारतीय समुद्री परंपरा और नौसैनिक गौरव का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। समारोह में मौजूद हजारों दर्शकों ने इस दृश्य का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ब्रुकलिन में प्रवास के दौरान आईएनएस सुदर्शिनी ने भारत के एक राजदूत की भूमिका निभाई। जहाज पर 1,000 से अधिक लोगों ने भ्रमण किया, जिनमें भारतीय मूल के नागरिक, स्थानीय अमेरिकी निवासी, समुद्री इतिहास

ईरान का दावा : अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की मौत

विश्व केसरी

तेहरान। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि बुधवार से शुरू हुए अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार, ये हमले ईरान के पांच प्रांतों में किए गए।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता होसैन केरमनपौर ने बताया कि घायलों में से 47 अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं और राहत कार्यों को तेज कर दिया गया है।

इस बीच, ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्र स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं।

ईरानी सेना के अनुसार, इन हमलों में कुवैत में पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, कतर में प्रारंभिक चेतावनी (अर्ली वार्निंग) सैटेलाइट एंटीना साइट, और बहरीन में अमेरिकी सेना के ईंधन भंडारण टैंकों को निशाना बनाया गया। सेना का कहना है कि इन अभियानों में विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।

ईरानी सशस्त्र बलों ने एक बयान में कहा कि वे 'अमेरिकी राष्ट्रपति के उद्देश्यों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे' और देश की सुरक्षा तथा इस्लामी क्रांति के आदर्शों की रक्षा के लिए अपने अभियान जारी रखेंगे।

हालांकि, ईरान के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अमेरिका, बहरीन, कतर और कुवैत की ओर से भी इन कथित ड्रोन हमलों और संभावित नुकसान को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमेरिका ने बुधवार रात ईरान पर फिर एयरस्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने भी दावा किया कि उसने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल-ड्रोन स्टोरेज साइट, सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

युद्ध और संकट के बीच 'उम्मीदों वाली खुशबू', जाफा की मशहूर अबुलाफिया बेकरी को शांति की आस

विश्व केसरी

जाफा (इजरायल)। इजरायल के ऐतिहासिक शहर जाफा स्थित अबुलाफिया बेकरी केवल पारंपरिक मध्य-पूर्वी व्यंजनों के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मेल-जोल की मिसाल के रूप में भी पहचानी जाती है। इस बेकरी के सीईओ सैद अबुलाफिया का कहना है कि उनका प्रतिष्ठान वर्षों से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों समुदायों के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। यहां इजरायल में रह रहे भारतीय भी इस बेकरी के मुरीद हैं।

आईएएनएस से बातचीत में सैद ने वर्तमान समय में आ रही चुनौतियों के बीच 'उम्मीदों वाली खुशबू' फैलाने का राज बताया। उन्होंने कहा, अबुलाफिया परिवार मुस्लिम अरब परिवार है, लेकिन उनके ग्राहकों में सभी धर्मों के लोग

शामिल हैं। बेकरी को यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समान रूप से पसंद करते हैं। इजरायल में काम करने वाले कई भारतीय भी, खासकर डायमंड एक्सचेंज से जुड़े कर्मचारी, नियमित रूप से यहां आते हैं।

सैद अबुलाफिया बेकरी की छठी पीढ़ी की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने बताया, 1879 से हम इस बिजनेस में हैं। हमारी बेकरी में पारंपरिक मध्य-पूर्वी पेस्ट्री और बेकरी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इनमें तिल वाले बैगल्स, जातर के साथ पीटा ब्रेड और पनीर, फेटा चीज तथा आलू से भरे हुए सांबुसक जैसे लोकप्रिय व्यंजन शामिल हैं। बेकरी इजरायल में एक जाना-पहचाना ब्रांड बन चुकी है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा हालात का असर पर्यटन पर पड़ा है। अबुलाफिया के अनुसार, उनकी बेकरी के लगभग 15 प्रतिशत ग्राहक पर्यटक होते हैं, इसलिए पर्यटन में गिरावट का सीधा प्रभाव उनके कारोबार पर पड़ा। पिछले तीन वर्षों से पर्यटकों की संख्या काफी कम रही।

अबुलाफिया बेकरी उम्मीद का दामन थामे हुए है। बिगड़े हालात में भी कुछ बनाने और बनने की इच्छा बरकरार है। जैसा सैद कहते हैं, हाल में हुए संघर्षविराम (लेबनान) के बाद हालात में कुछ सुधार देखने को मिला है।

अमेरिका इतिहास की सबसे मजबूत आर्थिक तरक्की के दौर में : ट्रंप

विश्व केसरी

अंकारा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका इस समय अपने इतिहास की सबसे मजबूत आर्थिक बढ़त के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड निवेश, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी और बड़ी संख्या में नए रोजगार उनकी सरकार की नीतियों का नतीजा हैं, जो देश के औद्योगिक ढांचे को बदल रही हैं।

अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अपनी आर्थिक रफ्तार और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान फिर से हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि अब साफ दिख रहा है कि अमेरिका वापस आ गया है और पहले से ज्यादा मजबूत, बड़ा और बेहतर बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से ज्यादा नौकरियां हैं और दुनिया अब फिर से हमारा सम्मान करती है, शायद पहले कभी इतना नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि कंपनियों ने पूरे देश में नई फैक्ट्रियां और उत्पादन इकाइयां लगाने के लिए रिकॉर्ड स्तर का निवेश करने का फैसला किया है।

ट्रंप ने दावा किया कि हमारे यहां अब तक का सबसे बड़ा निवेश हुआ है 19.2 ट्रिलियन डॉलर का। यह पहले के मुकाबले छह गुना ज्यादा है। इतिहास में न तो अमेरिका में और न ही किसी दूसरे देश में ऐसा कभी हुआ है। ट्रंप के मुताबिक यह निवेश कई अहम उद्योगों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियां भी तेजी से फैक्ट्रियां बना रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से बढ़ने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एआई कंपनियों को हमने अपने खुद के बिजली संयंत्र बनाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस इंडस्ट्री को ही इतनी ऊर्जा चाहिए जितनी इस समय पूरा अमेरिका पैदा करता है। ट्रंप ने दावा किया कि एआई के क्षेत्र में अमेरिका अभी भी चीन से आगे है।

सिंधु जल संधि से नहीं, खराब प्रबंधन और भूजल दोहन की वजह से जल संकट से जूझ रहा पाकिस्तान : रिपोर्ट

विश्व केसरी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। लाहौर और पंजाब प्रांत के कई अन्य इलाकों में पानी की कमी और गंभीर होती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अपनी आंतरिक समस्याओं और जरूरत से ज्यादा भूजल निकालने जैसी वजहों पर ध्यान देने के बजाय इस्लामाबाद लगातार भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है।

यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था दुनिया की सबसे खराब व्यवस्थाओं में से एक है। नहरों में रिसाव और पानी की बर्बादी के कारण बड़ी मात्रा में पानी बेकार चला जाता है। रिपोर्ट में इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के 2024-2026 के आकलनों का हवाला देते हुए बताया गया कि पाकिस्तान के कुल मीठे पानी का करीब 95 प्रतिशत हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। वहीं, सिंचाई की खराब व्यवस्था और खेतों तक पानी पहुंचाने के पुराने तरीकों की वजह से लगभग 60 प्रतिशत सिंचाई का पानी बर्बाद हो जाता है। हाल ही में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया, जिसका विषय था — 'सिंधु जल संधि: शांति और क्षेत्रीय स्थिरता का एक साधन।

डीआर कांगो में इबोला वायरस का कहर जारी, 600 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा

विश्व केसरी

किंशासा। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इससे मरने वालों की संख्या 600 तक पहुंच गई है और 1,759 मामलों की पुष्टि हुई है। बुधवार देर रात जारी एक अपडेट में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अभी कुल 750 मरीज आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पतालों में 94 प्रतिशत बेड भरे हुए हैं।

बुंडीबुग्यो इबोला वायरस से होने वाला यह प्रकोप, जिसे 15 मई को घोषित किया गया था, देश का 17वां इबोला प्रकोप है। इसने तीन प्रांतों - इतुरी, नॉर्थ किवु और साउथ किवु - के 37 स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकोप से निपटने में कई बाधाएं आ रही हैं, जिनमें पोस्टमार्टम के लिए सैंपल लेने का समुदाय द्वारा विरोध, इलाज की अपर्याप्त क्षमता, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी, सीमित सप्लाई, असुरक्षा और हथियारबंद समूहों से प्रभावित इलाकों तक सीमित पहुंच शामिल हैं। डीआरसी ने मई के मध्य में इस प्रकोप की घोषणा की थी। स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि असुरक्षा, लोगों की आवाजाही, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव और अधूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण स्थिति से निपटना मुश्किल हो रहा है।

इबोला वायरस से होने वाली एक दुर्लभ, गंभीर और अक्सर जानलेवा बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों (जैसे फ्रूट बैट) से इंसानों में फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों (बॉडी फ्लूइड्स) के सीधे संपर्क से फैलता है। इसमें अचानक फ्लू जैसे लक्षण और बुखार आता है। इससे शरीर के अंग काम करना बंद कर सकते हैं। मई 2018 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला प्रकोप की पुष्टि हुई थी।

उपराष्ट्रपति ने हाई सीज फिशिंग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया, ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन भी लॉन्च

विश्व केसरी

भुवनेश्वर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हाई सीज (गहरे समुद्र) में सतत मत्स्य दोहन के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जारी करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी लॉन्च किया और देशभर के 10 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तथा मछुआरों को हाई सीज फिशिंग के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह पहल भारत की समुद्री यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इससे भारतीय मछुआरे देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र में मौजूद अपार समुद्री संसाधनों का सतत और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मछुआरा समुदाय के साझा प्रयासों का परिणाम है, जो मत्स्य क्षेत्र में विकास,

स्थिरता और समृद्धि के नए युग की शुरुआत करेगा।

उपराष्ट्रपति ने बताया कि भारत के पास 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इसके बावजूद समुद्र में मौजूद विशाल संसाधनों का अभी तक पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया है। अब तक मछली पकड़ने की गतिविधियां मुख्य रूप से तटीय इलाकों तक सीमित थीं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत भारतीय मछुआरे अब समुद्र की टूना जैसी उच्च मूल्य वाली मछलियों का सतत दोहन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और वैश्विक मछली उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत है। यह क्षेत्र देश के करीब तीन करोड़ मछुआरों और मत्स्य पालकों की आजीविका का आधार है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 73,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। उन्होंने विश्वास जताया कि हाई सीज पहल से निर्यात में और वृद्धि होगी तथा मछली पकड़ने, प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, परिवहन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात सेवाओं में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उपराष्ट्रपति ने बताया कि नई व्यवस्था में मत्स्य सहकारी समितियों, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय मछुआरों को प्राथमिकता के आधार पर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिए जाएंगे। उन्होंने इसे तटीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि सतत मत्स्य पालन केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। आर्थिक विकास के साथ समुद्री संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। उपराष्ट्रपति डिजिटल ऑथराइजेशन सिस्टम, जहाजों की ट्रैकिंग, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और अवैध, बिना रिपोर्टिंग तथा अनियमित मत्स्य पालन पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

एआई पर झारखंड सरकार पांच वर्षों में करेगी 1,150 करोड़ का निवेश, निवेशकों के बीच साझा किया रोडमैप

विश्व केसरी

नई दिल्ली/रांची। झारखंड सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार के जरिए राज्य को देश का अग्रणी एआई राज्य बनाने का रोडमैप प्रस्तुत किया है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में एआई अवसंरचना, डिजिटल क्षमता विस्तार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,150 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव रखा है। यह जानकारी नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दौरान साझा की गई।

सरकार ने प्रस्तावित 'झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति 2026-31' की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। नीति के तहत शासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खनन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे। साथ ही डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदार तकनीकी उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार के अनुसार, राज्य में एआई आधारित निर्णय प्रणाली विकसित कर सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (सीएम-डीआईपी) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं, आधारभूत

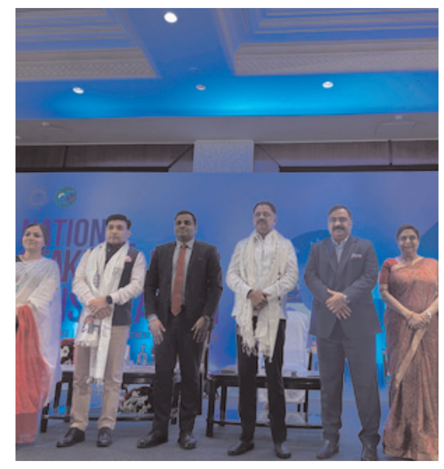

संरचना परियोजनाओं और विभागीय कार्यों की रियल टाइम निगरानी करेगा। इसके अलावा बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवाएं, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली और पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं के विस्तार की भी योजना है।

बैठक में मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (सीएम-डीआईपी), हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (एचएनवीएस) और क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (सीएमएएस) जैसी तीन प्रमुख एआई आधारित पहलों पर विशेष जोर दिया गया।

संक्षिप्त खबर

करूर दौरे पर सीएम विजय, भगदड़ पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात

विश्व केसरी

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय शुक्रवार को करूर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 2025 की करूर भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। साथ ही पात्र परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी औद्योगिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

यह दौरा 27 सितंबर, 2025 को वेलुचामिपुरम में टीवीके के एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ के करीब दस महीने बाद हो रहा है। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। यह हादसा हाल के वर्षों में तमिलनाडु में किसी राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हुई सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे चेन्नई से विमान से रवाना होंगे। तिरुची पहुंचने के बाद वह सड़क मार्ग से करूर जाएंगे। वहां उनका पहला कार्यक्रम करूर-सलेम बाईपास रोड स्थित एटलस कलैयारंगा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करना होगा। इस दौरान वह कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी करेंगे।

'नशामुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत बड़ी कार्रवाई, पुलवामा पुलिस ने नष्ट किए 150 किलो मादक पदार्थ

विश्व केसरी

पुलवामा। नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत पुलवामा पुलिस ने गुरुवार को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में जब्त किए गए भारी मात्रा में मादक पदार्थों को नष्ट किया। पुलिस ने कहा कि यह कदम राज्य को नशा मुक्त बनाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में उठाया गया है। पुलवामा पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों और साइकोट्रॉपिक दवाओं को आईजीसी लस्सीपोरा, पुलवामा स्थित एम/एस कश्मीर हेल्थ केयर सिस्टम के अधिकृत कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में नष्ट किया गया।यह पूरी प्रक्रिया एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के तहत गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी, पुलवामा की निगरानी में पूरी की गई। पुलिस के अनुसार, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और सक्षम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के बाद ही यह कार्रवाई की गई। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शी और कानून के तय नियमों के अनुसार संपन्न हुई।

शिक्षा निदेशालय का आदेश : कश्मीर में स्कूलों की किताबों से हटाई जाएगी आपत्तिजनक सामग्री

विश्व केसरी

श्रीनगर। जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पहले ही उन किताबों और रिसर्च मटीरियल की समीक्षा शुरू कर दी है जिनमें आपत्तिजनक सामग्री हो सकती है। वहीं, स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (डीएसईके) ने गुरुवार को सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग सेंटरों की सभी किताबों की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया।

कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी और सभी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में मौजूद किताबों, मैगजीन, जर्नल्स, रिसर्च मटीरियल और दूसरी चीजों की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि उनमें कोई

आपत्तिजनक कंटेंट न हो।

इस बीच, कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के साथ-साथ कोचिंग सेंटरों में मौजूद सभी किताबों की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि वहां परिसर में कोई आपत्तिजनक कंटेंट वाली सामग्री मौजूद न हो। आदेश के अनुसार, सभी संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑफिस, क्लासरूम, स्टाफ रूम और स्कूल लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की जांच करें, जिसमें हाल ही में खरीदी गई और पुरानी किताबें भी शामिल हैं।

सर्कुलर में कहा गया है कि इसका मकसद यह पक्का करना है कि किसी भी किताब में ऐसा कंटेंट न हो जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, छात्रों के लिए अनुपयुक्त सामग्री हो, मौजूदा कानूनों के खिलाफ हो, राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाए, या शैक्षिक मूल्यों और स्थापित मानदंडों पर असर डाले।

सभी सामग्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आयु-उपयुक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप भी होना चाहिए। यदि कोई आपत्तिजनक कंटेंट मिलता है, तो संस्थान के प्रमुख को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें किताब का शीर्षक, प्रकाशन का वर्ष, लेखक और प्रकाशक का नाम और किताबों की संख्या का उल्लेख हो।

संस्थानों से कहा गया है कि वे इस प्रक्रिया को पूरी सावधानी से पूरा करें और 13 जुलाई तक रिपोर्ट जमा करें।

पीएम मोदी ने भारत को सुशासन और स्थायित्व का वैश्विक ब्रांड बनाने का काम किया : मुख्तार नकवी

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को रेखांकित किया। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आज की तारीख में भारत की पहचान वैश्विक मंच पर अलग है।

उन्होंने गुरुवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सुशासन और स्थायित्व का वैश्विक ब्रांड बनाने का काम किया है। भारत आज की तारीख में वैश्विक ब्रांड संयोग से नहीं बना है, बल्कि यह उनके परिश्रम का नतीजा है। पूरी दुनिया में भारत की साख अगर बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

उनके मुताबिक, 2024 से पहले किस तरह से संकट की स्थिति बनी हुई थी, यह बात किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से कुछ लोगों ने राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में अवधारणाओं को प्रचारित करने की कोशिश

की गई, वो बात भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन, मैं समझता हूं कि इन तमाम दुश्वारियों को परास्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत की धाक और धमक को मजबूत करने का काम किया है, जिसकी वजह से उनकी कार्यशैली की प्रशंसा की जानी चाहिए। आज की तारीख में अमेरिका से लेकर अरब तक के लोगों का विश्वास भारत पर बढ़ा है, जिसे हम सभी लोगों को सकारात्मक संकेत के रूप में देखना चाहिए। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिसे लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, कोटे के लोटे से आरक्षण का अफीम पिलाने का धंधा अब खत्म हो चुका है।

मध्य प्रदेश में निर्माण कार्य में गड़बड़ी पर चार अफसरों को नोटिस और ठेकेदार का पंजीयन निलंबित

विश्व केसरी

भोपाल । मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन कराए जाने वाले कार्यों के निरीक्षण में कई गड़बड़ियां पाई गई है। जिस पर चार अफसर को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, वही ठेकेदारी का पंजीयन निलंबित किया गया है । आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी बताया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में औचक निरीक्षण किए जा रहे है।

बीते दिनों मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने रायसेन, पांढुर्णा, शिवपुरी, बुरहानपुर, उमरिया, मंदसौर एवं निवाड़ी जिलों में निर्माणाधीन एवं पूर्ण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कुल 34 निर्माण कार्यों का रेंडम आधार पर परीक्षण किया गया, जिनमें लोक निर्माण विभाग (सड़क

एवं पुल) के 21, पीआईयू के छह, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के छह तथा मध्यप्रदेश भवन विकास निगम का एक कार्य शामिल रहा। निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा प्रमुख अभियंता (सड़क व पुल) आर.एल. वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में की गई।

बैठक में प्रमुख अभियंता (एमपीआरडीसी) के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता (भवन) एस.आर. बघेल, प्रमुख अभियंता (बीडीसी) अजय श्रीवास्तव सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी निरीक्षण दल ऑनलाइन उपस्थित रहे। समीक्षा में बुरहानपुर जिले के सुंदर नगर-कुंदन डेयरी रोड स्थित पंडारोल नाला पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल के कार्य में गुणवत्ता संबंधी कमियां पाए जाने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं तत्कालीन कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह बुरहानपुर जिले में हिवरा फाटा-हैदरपुर फाटा सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी अपेक्षित स्तर की नहीं मिलने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री के विरुद्ध नोटिस जारी करने तथा कार्य कर रही एजेंसी मेसर्स कालिका फर्नीचर इंडस्ट्रीज, खंडवा के पंजीयन निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश प्रमुख अभियंता इंदौर को दिए गए।

झालावाड़ पुलिस ने 50 लाख की स्मैक-चरस के साथ तीन तस्करों को किया गिरफ्तार

विश्व केसरी

जयपुर। राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और नशे के कारोबार पर करारा प्रहार करते हुए 50 लाख रुपए की स्मैक और चरस बरामद की है। इसी के साथ झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक एवं चरस की तस्करी करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार कर 50 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीयय बाजार मूल्य की अवैध मादक पदार्थ स्मैक एवं चरस जब्त की है।

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि थानाधिकारी कोतवाली मुकेश मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी एनएच 52 देवरीघटा झालावाड से मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करते हुए तीन तस्करोंको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दो आरोपियों की पहचान नरेश गुर्जर और मोर सिंह

गुर्जर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनको 250 ग्राम के करीब अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जप्तशुदा मादक पदार्थ स्मैक की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है।

वहीं, पुलिस की ओर से की गई दूसरी कार्रवाई में तांबे की खान ईदगाह रोड पर मादक पदार्थ तस्कर शाहरूख को 86 ग्राम के करीब चरस सहित गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। उक्त तस्करों के विरूद्ध पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अभियुक्तों से अवैध मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। बता दें कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और ड्रग्स कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई का एक इसी प्रकार का दूसरा मामला मंगलवार को पंजाब से सामने आया, जहां पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर में एक ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।

अगर शरद पवार एनडीए में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे : योगेश कदम

विश्व केसरी

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हालिया मुलाकात के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम ने संजय राउत पर निशाना साधा और कहा कि शरद पवार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना यह दिखाता है कि संजय राउत किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते।

योगेश कदम ने कहा, संजय राउत कभी शिवसेना के नहीं थे, बल्कि वे शरद पवार के शिष्य रहे हैं। अब जब उन्हें अपने गुरु की कोई बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उन्हीं पर अविश्वास जताना

शुरू कर दिया।

जब उनसे पूछा गया कि यदि भविष्य में शरद पवार एनडीए में शामिल होते हैं तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा, इस पर योगेश कदम ने कहा, बिलकुल स्वागत करेंगे। शरद पवार ने महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किया है। आज वह राज्य के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। अगर वे एनडीए में आते हैं तो मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। वहीं, 'महाराष्ट्र मिसिंग लिंक' परियोजना को लेकर उठ रहे सवालों पर भी योगेश कदम ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह वही परियोजना है जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। कांग्रेस के पास न तो इसे पूरा करने का साहस था और न ही आर्थिक तथा तकनीकी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस चुनौतीपूर्ण परियोजना को सफल बनाया, जिसे कभी असंभव माना जाता था।

कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर 130 साल पुराना ऐतिहासिक क्लॉक टावर ढहा

प्लेटफॉर्म पर मलबा गिरा, कोई हताहत नहीं

विश्व केसरी

कोझिकोड। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। स्टेशन का करीब 130 साल पुराना ऐतिहासिक क्लॉक टावर अचानक भरभराकर गिर गया। टावर का भारी मलबा प्लेटफॉर्म नंबर-2 और ऊपर से गुजर रही बिजली की ओवरहेड लाइन पर आ गिरा। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वहां कोई यात्री मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

यह घटना गुरुवार की सुबह हुई। उस समय टावर के पास मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने इमारत को गिरते देखा और तुरंत वहां से हट गए। उनकी सतर्कता के कारण वे सुरक्षित बच निकले। हादसे के समय कोझिकोड-कन्नूर

पैसेंजर ट्रेन, जो दोपहर 2:05 बजे रवाना होने वाली थी, प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर खड़ी थी। हालांकि ट्रेन के दरवाजे बंद थे और उसमें अभी यात्रियों की चढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। इसी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म नंबर-2 और 3 के बीच स्थित क्लॉक टावर का एक हिस्सा और उसकी छत एक साथ गिर गई। मलबा गिरने से ओवरहेड बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ।

इस घटना के बाद मंगलुरु-तिरुवनंतपुरम एरानाड एक्सप्रेस को देरी का सामना करना पड़ा। एहतियात के तौर पर रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर-2 और 3 पर यात्रियों की आवाजाही रोक दी और पूरे क्षेत्र को खाली करा दिया।

प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण यह पुरानी इमारत कमजोर हो गई थी। गुरुवार सुबह भी कोझिकोड में तेज बारिश जारी थी, जिससे ढांचा और कमजोर पड़ गया। इस घटना ने रेलवे के पुराने ढांचों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इमारत में पहले से दरारें दिखाई दे रही थीं और यह भी माना जा रहा था कि उम्र के कारण इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक, रेलवे अधिकारियों ने गुरुवार सुबह ही क्लॉक टावर का निरीक्षण किया था और उसकी मरम्मत या सुरक्षा को लेकर चर्चा भी चल रही थी। स्टेशन पर इन दिनों पुनर्विकास कार्य चल रहा है, जिसमें पाइलिंग का काम भी शामिल है। पहले भी यह चिंता जताई गई थी कि इन कार्यों से पैदा होने वाले कंपन (वाइब्रेशन) पुराने ढांचे को और कमजोर कर सकते हैं। आलोचकों का आरोप है कि बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

एआई की ओर बढ़ते कदमों के बीच चीन की बड़ी टेक कंपनियों ने 18 महीने में की 1.3 लाख कर्मचारियों की छंटनी: रिपोर्ट

विश्व केसरी

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को तेजी से अपनाने और कंपनियों के पुनर्गठन के बीच चीन की प्रमुख टेक कंपनियों ने पिछले डेढ़ साल में करीब 1.3 लाख कर्मचारियों की छंटनी की है। एक नई रिपोर्ट में इतने बड़े स्तर पर हो रही नौकरी कटौती पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की चुप्पी आलोचना की गई है।

श्रीलंका स्थित डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, अलीबाबा, टेनसेंट, बाइटडांस, मीतुआन और बायडू जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। इनमें यात्रा, कंटेंट और ई-कॉमर्स सपोर्ट से जुड़े कुछ विभागों में कर्मचारियों की संख्या 30 से 50 प्रतिशत तक घटा दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 18 महीनों में इन पांच प्रमुख इंटरनेट कंपनियों ने मिलकर 1.3 लाख से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अलीबाबा के कर्मचारियों की संख्या करीब 1.94 लाख से घटकर 1.28 लाख रह गई, यानी लगभग 34 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, बायडू ने करीब 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जबकि जेडी डॉट कॉम करीब 12,000 नौकरियां खत्म करने की योजना बना रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार की छंटनी इसलिए ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि यह कंपनियों के घाटे में होने के कारण नहीं, बल्कि मुनाफा बढ़ने के बावजूद की जा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'पहले कंपनियां अस्तित्व बचाने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाती थीं, लेकिन अब वे अपने कारोबार को अधिक कुशल बनाने के लिए ऐसा कर रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां यह कदम एआई-आधारित उत्पादों और सेवाओं की ओर तेजी से बढ़ने की अपनी रणनीति के तहत उठा रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग का 'एआई प्लस एक्शन प्लान' वर्ष 2027 तक प्रमुख उद्योगों में 70 प्रतिशत और 2030 तक 90 प्रतिशत एआई उपयोग का लक्ष्य रखता है। अलीबाबा का 'वुकोंग' प्लेटफॉर्म जैसे एआई टूल्स ई-कॉमर्स, लाइव स्ट्रीमिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में पूरे विभाग का काम स्वचालित करने और 'वन-पर्सन कंपनी' मॉडल को संभव बनाने का दावा करते हैं।

विशेषज्ञों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में लगभग 7 करोड़ नौकरियां, जो देश के कुल कार्यबल का करीब 9.6 प्रतिशत हैं, एआई के कारण जोखिम में हैं। इसमें सबसे अधिक खतरा युवा कर्मचारियों को बताया गया है।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन में अनौपचारिक रूप से '35 वर्ष की उम्र की सीमा' जैसी स्थिति बन गई है। इसके तहत 35 वर्ष के आसपास के कर्मचारियों, जिन पर परिवार, होम लोन और बच्चों की जिम्मेदारी होती है, उन्हें बड़े पैमाने पर नौकरी से निकाला जा रहा है।

रिपोर्ट में बाइटडांस के 26 वर्षीय एक पूर्व कर्मचारी का भी उल्लेख किया गया है, जिसे कंटेंट ऑपरेशंस में छह साल काम करने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारी के अनुसार, पहले कंपनी का नाम प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था, लेकिन वास्तविकता में लगातार ओवरटाइम और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। अब बड़ी टेक कंपनी का अनुभव भी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं रहा।

गुजरात: मिलावटी प्लाज्मा जब्त, 'इंसानों के इस्तेमाल के लायक नहीं' घोषित; महाराष्ट्र के ब्लड बैंकों तक बढ़ी जांच

विश्व केसरी

अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में सामने आए ब्लड प्लाज्मा में मिलावट के रैकेट की जांच कर रहे अधिकारियों को पता चला कि मुख्य आरोपी के घर से जब्त किए गए सभी 1,140 प्लाज्मा यूनिट मिलावटी, घटिया क्वालिटी के और इंसानों के इस्तेमाल के लायक नहीं थे।

इसके बाद अधिकारियों ने जब्त किए गए स्टॉक को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जांच का दायरा महाराष्ट्र के कई ब्लड बैंकों तक बढ़ा दिया है।

अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने सोमवार को बताया कि बीजे मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि मुख्य आरोपी दिनेश चौधरी के घर से बरामद प्लाज्मा यूनिट्स, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के तय मानकों पर खरे नहीं उतरे।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'प्लाज्मा बहुत खराब क्वालिटी का था, इससे इंसानी जान को खतरा हो सकता था और यह ट्रांसफ्यूजन के लिए सही नहीं था।' इन नतीजों के आधार पर जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपी ने जिसे असली प्लाज्मा बताकर बेचा था, उसमें भी चोरी के बाद मिलावट की गई थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने असली प्लाज्मा यूनिट्स से अच्छी क्वालिटी का कुछ प्लाज्मा निकाल लिया और उसकी मात्रा को बनाए रखने के लिए बाकी बचे हिस्से में सलाइन वॉटर (नमक वाला पानी) मिला दिया, जिससे प्लाज्मा की क्वालिटी कम हो गई।

जब भी असली प्लाज्मा की नई खेप आती थी तो आरोपी उन्हें पहले से मिलावट किए गए प्लाज्मा यूनिट से बदल देते थे, ताकि सप्लाई की गई यूनिट्स की संख्या फार्मास्युटिकल कंपनी के ऑर्डर के बराबर रहे।

जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि खेप से निकाले गए असली प्लाज्मा में भी महाराष्ट्र के दो ब्लड बैंकों को बेचने से पहले मिलावट की जाती थी, जिससे आरोपी मात्रा बढ़ा सकते थे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओम प्रकाश जाट ने बताया कि इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की पूछताछ से पता चला है कि आरोपियों ने न केवल बदले गए प्लाज्मा में, बल्कि चुराए गए असली प्लाज्मा में भी मिलावट की थी।

जाट ने कहा, 'असली प्लाज्मा को नकली प्लाज्मा से बदलने और असली चुराने के बाद उन्होंने असली प्लाज्मा में भी मिलावट की। मिलावट के बाद, प्लाज्मा को महाराष्ट्र के दो ब्लड बैंकों में भेजा गया। ये वाशिम ब्लड बैंक और जालना ब्लड बैंक हैं।

एआरएफआईडी से जूझ रहे बच्चों का इलाज संभव, स्टैनफोर्ड की नई रिसर्च में मिले सकारात्मक नतीजे

विश्व केसरी

नई दिल्ली। आजकल बच्चों में सिर्फ 'पिकी ईटिंग ', यानी चुन-चुनकर खाना खाने की आदत ही नहीं, बल्कि एक गंभीर स्थिति भी देखने को मिल रही है, जिसे एआरएफआईडी (अवायडेंट रेस्ट्रिक्टिव फ़ूड इनटेक डिसऑर्डर) कहा जाता है। स्टैनफोर्ड मेडिसिन के वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में इस बीमारी के इलाज को लेकर बड़ी सफलता मिली है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, यह पहली बार है कि एआरएफआईडी जैसे खान-पान संबंधी विकार के उपचार का मूल्यांकन रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल के जरिए किया गया है। यह अध्ययन 6 से 12 वर्ष की आयु के 98 बच्चों पर किया गया। इसके निष्कर्ष 'जर्नल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री' में प्रकाशित हुए हैं।

एआरएफआईडी से पीड़ित बच्चे भोजन में बहुत कम रुचि दिखाते हैं या फिर उन्हें खाने से डर लगता है। कई मामलों में यह समस्या बचपन से ही शुरू हो जाती है और समय पर इलाज न मिलने पर बच्चों के शारीरिक विकास पर असर पड़ सकता है।

अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता जेम्स लॉक ने कहा कि पहली बार इस बीमारी के उपचार का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया गया है। उनके अनुसार, अब ऐसा वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध है जिसकी मदद से खासकर उस आयु वर्ग के बच्चों का बेहतर इलाज किया जा सकता है, जिसमें यह समस्या

सबसे अधिक देखी जाती है।

इस रिसर्च में दो तरह की थेरेपी को टेस्ट किया गया। पहली थी फैमिली-बेस्ड थेरेपी और दूसरी थी इंडिविजुअल मोटिवेशनल थेरेपी। दोनों ही ट्रीटमेंट ऑनलाइन दिए गए और हर बच्चे को चार महीने तक 14-14 सेशन मिले।

फैमिली-बेस्ड थेरेपी में माता-पिता को मुख्य भूमिका दी गई। उन्हें सिखाया गया कि बच्चे की खाने की आदतों को कैसे धीरे-धीरे बदलें। पूरा परिवार (माता-पिता, भाई-बहन और थेरेपिस्ट) एक साथ सेशन में शामिल होते थे। इसमें यह भी समझाया जाता था कि बच्चा जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि यह एक मेडिकल कंडीशन है।

दूसरी तरफ, इंडिविजुअल थेरेपी में बच्चे को खुद मोटिवेट किया जाता था।

इसमें बच्चों के साथ गेम्स, एक्टिविटी और कल्पना आधारित अभ्यास कराए जाते थे, जैसे कि काल्पनिक रेस्टोरेंट बनाना या अलग-अलग देशों के खाने के बारे में सोचना, ताकि उनकी खाने में रुचि बढ़े।

रिसर्च के नतीजे दिलचस्प रहे। जिन बच्चों ने फैमिली-बेस्ड थेरेपी ली, उनका वजन ज्यादा तेजी से बढ़ा और उनकी सेहत में सुधार दिखा। वहीं दोनों ही ग्रुप्स में एआरएफआईडी के लक्षणों में सुधार हुआ, यानी दोनों तरीके काफी हद तक कारगर पाए गए।

एडवांस्ड सेल और जीन थेरेपी के नियमन के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल्स में किया संशोधन

विश्व केसरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एडवांस्ड सेल और जीन थेरेपी जैसी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के नियमन को और प्रभावी बनाने के लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सेल या स्टेम सेल से बने उत्पादों, जीन थेरेपी उत्पादों और जेनोग्राफ्ट्स को सेंट्रली लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी (सीएलएए) के दायरे में शामिल किया गया है।

सरकार का कहना है कि इस कदम से पूरे देश में इन आधुनिक चिकित्सा उत्पादों के लिए एक समान नियामक व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सरकार के अनुसार, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कुछ महत्वपूर्ण दवाओं और जैविक उत्पादों की निगरानी पहले से ही केंद्र और राज्य सरकारों की लाइसेंसिंग एजेंसियां मिलकर करती हैं। इनमें वैक्सीन, 100 मिलीलीटर से अधिक मात्रा वाले इंट्रावीनस (आईवी) सॉल्यूशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आधारित दवाएं शामिल हैं। अब इस व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर नई चिकित्सा तकनीकों को भी इसमें शामिल किया गया है।

सरकार ने बताया कि सेल और स्टेम सेल आधारित उत्पादों का उपयोग रीजेनरेटिव थेरेपी और सीएआर-टी सेल थेरेपी जैसे आधुनिक उपचारों में तेजी से बढ़ रहा है। इनका इस्तेमाल ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। वहीं, जीन थेरेपी उत्पादों का उपयोग जीन रिप्लेसमेंट और जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों के जरिए आनुवंशिक बीमारियों और कई प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जा रहा है।

इसके अलावा, जेनोग्राफ्ट्स ऐसे चिकित्सा उत्पाद हैं, जो जानवरों के ऊतकों से तैयार किए जाते हैं। इनमें हार्ट वॉल्व जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल कार्डियोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स में प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है।

सरकार का कहना है कि ये सभी तकनीकें तेजी से विकसित हो रही हैं और काफी जटिल हैं। ऐसे में इनके सुरक्षित इस्तेमाल और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी जरूरी है। इन उत्पादों को सीएलएए के दायरे में लाने से केंद्र और राज्य की लाइसेंसिंग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और पूरे देश में एक समान नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सरकार का मानना है कि यह संशोधन भारत के नियामक ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत करेगा। साथ ही, इससे स्वास्थ्य और लाइफ साइंसेज क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को सुरक्षित तरीके से अपनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस संबंध में विस्तृत राजपत्र (गजट) अधिसूचना भी जारी कर दी है।

ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहीं क्रॉनिक और मानसिक बीमारियां, एआईएचडब्ल्यू रिपोर्ट में चिंताजनक खुलासा

विश्व केसरी

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में दीर्घकालिक (क्रॉनिक)और मानसिक बीमारियां तेजी से लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं। यह जानकारी गुरुवार को जारी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर (एआईएसडब्ल्यू) की ऑस्ट्रेलिया हेल्थ रिपोर्ट 2026 में सामने आई है।

हर दो साल में जारी होने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में क्रॉनिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में ऑस्ट्रेलिया की 61 प्रतिशत आबादी यानी 1.54 करोड़ लोग कम से कम एक पुरानी बीमारी के साथ जीवन बिता रहे थे। वहीं 38 प्रतिशत लोग दो या उससे अधिक पुरानी बीमारियों से जूझ रहे थे।

एआईएसडब्ल्यू के मुताबिक, 2024 में ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने पुरानी बीमारियों के कारण लगभग 49 लाख (4.9 मिलियन) स्वस्थ जीवन वर्ष गंवा दिए। यह देश में कुल डिजीज बर्डन (रोग भार) का 84 प्रतिशत हिस्सा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में बीमारी

के बोझ के पांच सबसे बड़े कारण सभी क्रॉनिक बीमारियां थीं। इनमें डिमेंशिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मौत का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया।

इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी आंकड़ों में बताया गया था कि 2024 में देश में हुई कुल मौतों में 9.4 प्रतिशत मौतें डिमेंशिया के कारण हुईं, जबकि हृदय रोग से 8.7 प्रतिशत मौतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से 2024 के बीच डिमेंशिया से होने वाली मौतों में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में हृदय रोग से होने वाली मौतों में 18 प्रतिशत की कमी आई है। एआईएचडब्ल्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोरान बोलेविच ने इसका प्रमुख कारण ऑस्ट्रेलिया की बुजुर्ग होती आबादी को बताया।

रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में 16 से 85 वर्ष आयु वर्ग के 22 प्रतिशत लोगों ने बताया कि पिछले 12 महीनों में उन्हें किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं, 16 से 24 वर्ष के युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की दर 2007 के 26 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 39 प्रतिशत हो गई।

हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन चुनौतियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य सेवाओं के कारण लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार जारी है।

बारिश के मौसम में सेहत का रखें खास ख्याल, ऋतुचर्या के अनुसार बदलें खान-पान और दिनचर्या की आदतें

विश्व केसरी

नई दिल्ली। वर्षा ऋतु का मौसम अपने साथ ठंडक और ताजगी लेकर आता है, लेकिन इसी समय शरीर के अंदर कई बदलाव भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, इस मौसम में पाचन शक्ति, यानी जठराग्नि, थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए जो भी हम खाते-पीते हैं उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी वजह से ऋतुचर्या का पालन करना बहुत जरूरी माना गया है, ताकि शरीर संतुलित और रोगों से सुरक्षित रह सके।

आयुष मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि इस मौसम में हल्का, ताजा और आसानी से पचने वाला भोजन करना सबसे अच्छा होता है। भारी, तला-भुना और बासी खाना पाचन को और कमजोर कर सकता है। बरसात में नमी और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए बाहर का या खुला हुआ खाना खाने से बचना चाहिए। घर का बना सादा भोजन, जैसे मूंग दाल, उबली हुई सब्जियां और हल्के मसालों वाला खाना शरीर के लिए बेहतर माना जाता है।

आयुर्वेद यह भी कहता है कि इस मौसम में खट्टा और नमकीन स्वाद सीमित मात्रा में लेना चाहिए। वहीं, दूध और दही जैसी चीजों का सेवन सोच-समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये कफ को बढ़ा सकती हैं और जुकाम या भारीपन जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं।

पानी पीने के तरीके में भी बदलाव जरूरी है। इस मौसम में उबला हुआ या हल्का गुनगुना पानी पीना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। सुबह की शुरुआत अगर गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर की जाए तो यह शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन को सुधारने में मदद करता है।

वर्षा ऋतु में योग और हल्का व्यायाम भी बहुत लाभदायक होता है। इससे शरीर सक्रिय रहता है और जठराग्नि संतुलित बनी रहती है। वज्रासन, त्रिकोणासन, सेतुबंधासन और पादहस्तासन जैसे आसान योगासन इस मौसम में विशेष रूप से उपयोगी माने जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कई अहम पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में दी छूट

विश्व केसरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और पूंजीगत मशीनों (कैपिटल गुड्स) के आयात पर कस्टम ड्यूटी में राहत देने का फैसला किया है, जिसके पीछे का उद्देश्य स्मार्टफोन, लिथियम-आयन बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण की लागत कम करना तथा घरेलू विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को बढ़ावा देना है। इस संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं

(नोटिफिकेशन) जारी की हैं। इनके जरिए कस्टम ड्यूटी में छूट और रियायती शुल्क के दायरे में आने वाले सामानों की सूची का विस्तार किया गया है।

सरकार ने एक अधिसूचना के तहत ऑटोमोबाइल, मेडिकल और औद्योगिक उपयोग के लिए डिस्प्ले असेंबली बनाने में इस्तेमाल होने वाले पांच प्रमुख कंपोनेंट्स को 31 मार्च 2029 तक मूल सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) से छूट दी है, जिनमें डिस्प्ले सेल, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेंबली (एफपीसीए), बैकलाइट यूनिट, फ्रेम और एनिसोट्रॉपिक कंडक्टिव फिल्म (एसीएफ) शामिल हैं।

हालांकि, यह छूट मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, स्मार्ट मीटर, टीवी पैनल और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होने वाली डिस्प्ले असेंबली पर लागू नहीं होगी।

चित्रा के. सोमन: कड़ी मेहनत से बनाई पहचान, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, ग्रांड प्रिक्स में भी लहराया परचम

विश्व केसरी

नई दिल्ली। कुछ खिलाड़ियों में टैलेंट कूट-कूटकर भरा होता है, तो कुछ खिलाड़ी कड़ी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसी ही खिलाड़ी रहीं चित्रा.के.सोमन, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर 400 मीटर की दौड़ में देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन किया।

चित्रा का जन्म 10 जुलाई, 1983 को केरल के कोट्टायम में हुआ। चित्रा को शुरुआत से ही दौड़ने का काफी शौक था। वह स्कूल स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थीं। जल्द ही उनकी काबिलियत को कोच ने पहचाना और चित्रा ने बतौर धावक करियर बनाने का फैसला कर लिया। साधारण परिवार में जन्मीं चित्रा ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं।

साल 2004 में हुए एथेंस ओलंपिक में 4×400 मीटर रिले स्पर्धा में चित्रा ने हिस्सा लिया और वह सातवें स्थान पर रहीं। टीम स्पर्धा में उन्होंने मंजीत कौर, के.एम.बीनामोल और राजविंदर कौर के साथ मिलकर 4×400 मीटर रिले में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। टीम की साथी खिलाड़ियों संग मिलकर उन्होंने यह रिले 3:26.89 मिनट में पूरी की। इस प्रदर्शन ने विश्व स्तर पर उनको पहचान दिलाने का काम किया। साल 2006 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में चित्रा का प्रदर्शन लाजवाब रहा और वह सिल्वर मेडल जीतने वाली रिले टीम का हिस्सा रहीं।

इसके बाद, साल 2007 में हुई एशियाई ग्रांड प्रिक्स में भी चित्रा का जलवा देखने को मिला। उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 400 मीटर की दौड़ को चित्रा ने 51.30 सेकंड में पूरा किया, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। साल 2007 में चित्रा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय सरकार द्वारा 'अर्जुन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। चित्रा ने उस दौर में इस खेल में अपनी पहचान बनाई, जब काफी सीमित साधन हुआ करते थे। वह उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा बनीं, जो छोटे शहर से आकर अपने खेल के दम पर विश्व में पहचान बनाने की इच्छा रखती हैं।

पिकलबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हर्ष मेहता को मिली कप्तानी

विश्व केसरी

मुंबई । भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन (आईपीए) ने पिकलबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दा नांग शहर में खेला जाएगा। भारतीय टीम का चयन कड़े ट्रायल और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद किया गया है। यह टीम प्रोफेशनल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।

इस बार टीम की कमान अनुभवी खिलाड़ी हर्ष मेहता को सौंपी गई है। हर्ष लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय पिकलबॉल सर्किट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके अनुभव से टीम को काफी उम्मीदें हैं। हर्ष के साथ युवा खिलाड़ी अर्जुन सिंह भी टीम का हिस्सा हैं। अर्जुन अंडर-18 वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसी वर्ग की टीम की कप्तानी भी संभालेंगे।

पुरुष टीम में हर्ष मेहता, अर्जुन सिंह, अनीश फ्रोलियन और अमन पटेल को जगह मिली है। वहीं, महिला टीम में मिहिका यादव, आलिया इब्राहिम, पर्ल अमलसदीवाला और नाओमी अमलसदीवाला को शामिल किया गया है। टीम के कप्तान हर्ष मेहता ने चयन के बाद खुशी जताते हुए कहा कि प्रतिभा मैच जिताती है, लेकिन एकजुट टीम ही चैंपियन बनाती है। उन्होंने कहा कि पूरी टीम अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कप्तानी मिलने पर भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन का आभार भी जताया।

महिला टीम की खिलाड़ी पर्ल और नाओमी अमलसदीवाला ने पिछले एक साल में घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों ने महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में कई टूर्नामेंटों में पदक जीते हैं। नाओमी अमलसदीवाला और अर्जुन सिंह की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स में भारत की सबसे मजबूत जोड़ियों में मानी जा रही है। हाल के समय में इस जोड़ी ने विश्व रैंकिंग की शीर्ष टीमों को हराकर अपनी क्षमता साबित की है।

भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह भुल्लर ने कहा कि इस बार भारत के पास बेहद मजबूत और संतुलित टीम है। उन्होंने कहा कि हर्ष मेहता के नेतृत्व में अर्जुन, अनीश, अमन, आलिया, मिहिका, पर्ल अमलसदीवाला और नाओमी अमलसदीवाला जैसे खिलाड़ियों के रहते भारत सिर्फ मुकाबला करने नहीं, बल्कि खिताब जीतने के इरादे से वियतनाम जाएगा।

पिछले वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम इस बार नए उत्साह और बड़े लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सभी चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत तकनीकी कौशल, फिटनेस, मानसिक मजबूती और सही खेल पोषण पर ध्यान देते हुए।

इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास के बाद नेमार के क्लब करियर पर भी सस्पेंस, सैंटोस ने फैसला लेने की खातिर दिया समय

विश्व केसरी

रियो डी जनेरियो। ब्राजील के फीफा वर्ल्ड कप के राउंड-ऑफ-16 से बाहर होने और स्टार फुटबॉलर नेमार के अंतरराष्ट्रीय संन्यास के ऐलान के बाद अब उनके क्लब करियर को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। ब्राजील मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बचपन के क्लब सैंटोस ने नेमार को अपने भविष्य पर विचार करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी है और उनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 34 वर्षीय नेमार के सैंटोस के साथ मौजूदा अनुबंध में अभी छह महीने का समय बाकी है। हालांकि स्थानीय मीडिया में इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद वह क्लब स्तर पर भी खेलना जारी रखेंगे या नहीं। बताया गया है कि सैंटोस प्रबंधन छुट्टियों के बाद नेमार और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके अगले कदम पर चर्चा करेगा।

नेमार फिलहाल अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही समय बिताएंगे और उन्हें कम से कम 10 दिनों का अवकाश दिया गया है। उन्होंने रविवार को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में नॉर्वे के खिलाफ 2-1 की हार के बाद ब्राजील की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की थी।

फीफा विश्व कप: मोरक्को को झटका, फॉरवर्ड सैबारी फ्रांस के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल से हुए बाहर

विश्व केसरी

नई दिल्ली। फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले मोरक्को को बड़ा झटका लगा है। उनके मुख्य फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी चोट के कारण इस अहम मैच से बाहर हो गए हैं।

मोरक्को के हेड कोच मोहम्मद ओआबी ने गुरुवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैबारी के बाहर होने की पुष्टि की। ओआबी के अनुसार, कनाडा के खिलाफ राउंड ऑफ 16 की जीत के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगने के बाद यह फॉरवर्ड समय पर ठीक नहीं हो सका। हालांकि, कोच को उम्मीद है कि अगर उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो 25 वर्षीय खिलाड़ी फिट हो जाएगा।

मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ओआबी ने कहा, 'वह तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए टूर्नामेंट का अंत नहीं है।'

सैबारी मौजूदा टूर्नामेंट में अफ्रीकी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने ग्रुप स्टेज के तीनों मैचों में गोल किए और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड के खिलाफ निर्णायक शूटआउट में पेनल्टी को गोल में बदला। उनकी अनुपस्थिति के कारण मोरक्को को 2022 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम के खिलाफ अधिक रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ सकती है।

फीफा ने फ्रांस और मोरक्को के बीच क्वार्टर-फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह से अर्जेंटीना के अधिकारियों की टीम नियुक्त करके एक बड़ी बहस छेड़ दी है। 2026 टूर्नामेंट में यह पहली बार है जब किसी मैच का संचालन पूरी तरह से एक ही देश के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। हालांकि, मोरक्को के कोच ने अधिकारियों के प्रभाव को कम करके आंका है।

मैच से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरी के बारे में उन्होंने कहा, 'हम एक बहुत अनुभवी रेफरी की बात कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं। हम इस तरह के मैचों के लिए अनुभवी रेफरी चाहते हैं। इसलिए हम बहुत शांत हैं। नीदरलैंड्स का सामना करने से पहले हमारे मैच में एक डच रेफरी था और उसने बहुत अच्छा काम किया था। हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि वे बस अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे होते हैं।

विंबलडन: 'वाइल्ड कार्ड' फेरी ने कोबोली को शिकस्त देकर उलटफेर किया, सेमीफाइनल में ज्वेरेव से होगा सामना

विश्व केसरी

लंदन । ब्रिटेन के आर्थर फेरी ने विंबलडन 2026 में अपना शानदार सफर जारी रखते हुए फ्रेंच ओपन 2026 के रनर-अप फ्लेवियो कोबोली को 6-4, 7-6(4), 6-0 से मात देकर पुरुषों के सेमीफाइनल में जगह बना ली। आर्थर ऐसा करने वाले इतिहास के दूसरे वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं।

शुक्रवार को ऑल इंग्लैंड क्लब में होने वाले सेमीफाइनल में फेरी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त और रोलैंड गैरोस चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा, जिन्होंने छठी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4, 6-2 से हराया था।

बुधवार को फेरी ने अपने घरेलू ग्रैंड स्लैम में बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा। आर्थर ने इटली के कोबोली को 2 घंटे और 14 मिनट तक चले मुकाबले में मात दी। इसी के साथ आर्थर क्रोएशियाई दिग्गज गोरान इवानिसेविच की बराबरी करते हुए विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए। 23 वर्षीय ब्रिटिश खिलाड़ी ने लंदन की चिलचिलाती धूप में शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने टॉप-10 स्टार कोबोली को हराया और एसडब्ल्यू19 में सबसे कम रैंकिंग वाले मेंस सिंगल्स सेमीफाइनलिस्ट बने। उनसे पहले, साल 2001 में तत्कालीन वर्ल्ड नंबर 125 गोरान इवानिसेविच ने खिताब जीता था।

फेरी 'ओपन एरा' में विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पांचवें ब्रिटिश पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले रोजर टेलर, टिम हेनमैन, एंडी मरे और कैमरून नॉरी ऐसा कर चुके हैं। एक तरफ, फेरी ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है, तो दूसरी ओर, ज्वेरेव ने भी अपने शानदार सीजन को जारी रखते हुए कुछ अहम उपलब्धियां हासिल कीं। डेढ़ महीने पहले रोलैंड गैरोस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद, यह जर्मन खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचा।

अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ मुकाबले में फ्रिट्ज दाएं घुटने की उसी चोट के दोबारा उभरने से जूझ रहे थे।

वैभव सूर्यवंशी के सामने हर गेंदबाज शॉर्ट गेंद के इस्तेमाल की कोशिश करेगा: पार्थिव पटेल

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल का मानना ??है कि युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शॉर्ट-पिच गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वैभव के खिलाफ इंग्लैंड का प्लान आईपीएल से ही स्पष्ट था और यह विरोधी गेंदबाजों के लिए पसंदीदा तरीका बना रहेगा।

पार्थिव पटेल ने जियो हॉटस्टार से कहा, 'सिर्फ जोफ्रा आर्चर ही नहीं, मुझे लगता है कि जिसने भी आईपीएल देखा है, उसे हैरानी नहीं होगी कि वैभव सूर्यवंशी को शॉर्ट गेंदबाजी करने का एक प्लान बनाया गया है। पहले गेम में, जिस गेंद पर उन्होंने छक्का मारा था, वह शायद उतनी बाउंस नहीं हुई होगी, लेकिन लाइन वही थी।

उन्होंने कहा, 'जैसे-जैसे वैभव सूर्यवंशी अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में आगे बढ़ेंगे, उन्हें इस तरह की गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें शॉर्ट और 145 किलोमीटर/घंटा से ज्यादा की गति वाली गेंदबाजी शामिल हैं। सवाल यह है कि वह शॉर्ट-पिच गेंदबाजी का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि हर गेंदबाज उन्हें उसी गेंद से टारगेट करने की कोशिश करेगा।'

पटेल ने कहा, 'मैं ब्रिस्टल में भारतीय बल्लेबाज से गेम की बेहतर समझ और गेम के बारे में थोड़ी और जानकारी देखना चाहूंगा। आप एक या दो ओवर खेलकर अच्छा खेल सकते हैं। कंडीशन अलग हैं, विकेट उतने फ्लैट नहीं हैं, और आपको ग्राउंड के आकार और विकेट की पेस की आदत डालनी होगी। इसलिए, खुद को कुछ समय देना बहुत जरूरी है।

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह तीसरा टी20 भी खेले थे। वैभव आईपीएल में मिली असाधारण सफलता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पहले दो मैचों में नहीं दोहरा पाए हैं। अपने डेब्यू मैच में 10 गेंदों पर 14 रन बनाने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी दूसरी पारी में 5 गेंदों पर 13 रन बनाए थे।

फीफा वर्ल्ड कप: क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले बढ़ी इंग्लैंड की मुश्किलें, रीस जेम्स के खेलने पर संशय बरकरार

विश्व केसरी

कैनसस सिटी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल मुकाबले से पहले इंग्लैंड फुटबॉल टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम के स्टार डिफेंडर रीस जेम्स का नॉर्वे के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलना अभी तय नहीं है। हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे जेम्स बुधवार को भी टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाए।

रीस जेम्स को घाना के खिलाफ इंग्लैंड के दूसरे ग्रुप मुकाबले के दौरान चोट लगी थी। गोलरहित ड्रॉ रहे इस मैच के बाद से वह टीम से बाहर हैं। वह रविवार को मेक्सिको के खिलाफ खेले गए राउंड ऑफ-16 मुकाबले में भी मैदान पर नहीं उतर सके थे। इंग्लैंड ने इस मैच में मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई है।

इंग्लैंड के कोच थॉमस ट्यूशेल के लिए डिफेंस को लेकर चिंता बढ़ गई है। मेक्सिको के खिलाफ मैच में जेरेल क्वांसाह को रेड कार्ड मिला था, जिसके कारण वह नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में राइट-बैक पोजीशन पर टीम के पास विकल्प सीमित हो गए हैं। मेक्सिको पर रोमांचक जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आराम और रिकवरी का समय दिया गया था। इसके बाद टीम के ज्यादातर खिलाड़ी स्वोप सॉकर विलेज में ट्रेनिंग के लिए लौटे। हालांकि, मार्क गुएही, रीस जेम्स और डेक्लान राइस ने सुबह के अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया। ये खिलाड़ी पहले से ही अलग-अलग व्यक्तिगत कार्यक्रम के तहत काम कर रहे थे।

डेक्लान राइस ने संकेत दिया है कि वह थोड़ी परेशानी के बावजूद खेलने के लिए तैयार हैं। वहीं, गुएही की गैरमौजूदगी को मांसपेशियों की थकान से जोड़ा गया है। इस बीच, अनुभवी मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन भी टीम के साथ बने हुए हैं। मेक्सिको के खिलाफ जीत का जश्न मनाने के दौरान उनकी कलाई में गंभीर चोट लगी थी। उनकी सफल सर्जरी के बाद वह वापस इंग्लिश कैंप में लौट आए हैं। टीम ने बताया ।

स्वात्वधिकारी राइवल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुजीत कुमार द्वारा साई प्रींटिंग प्रेस, डी-85, सेक्टर 6 नोएडा,गौतम बुध्द नगर पिन कोड -201301 उ.प्र. से मुद्रित और मकान संख्या एन-58 जगतराम पार्क के सामने, लक्ष्मी नगर पूर्व दिल्ली-110053 से प्रकाशित
समाचार संपादक : चन्द्रमणी साव (पीआरबी एक्ट के अनुसार समाचार पत्र चयन एवं संपादन के लिए उत्तरदायी। नोट किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा) मोबाइल 9340573892 ई-मेल: vishwakesari2026@gmail.com,आर.एन.आई.नं. DLHIN/2015/61415